- 19th Year
- Issue: 240
- 05.01.2026 (MONDAY)
- ROURKELA
- R.N.I. No. ORIHIN/2006/18978
- (Pages-6)
- Price:2.00

दैनिक कलिंग समाचार

The kalingasamachar

e-paper-www.thekalingasamachar.com

प्रकाशक एवं संपादक : प्रकाश कुमार धल

Published From ODISHA, JHARKHAND & CHHATTISHGARH

वॉलीबॉल कोर्ट से ओलंपिक तक, काशी में नेशनल चैंपियनशिप के उद्घाटन पर नरेंद्र मोदी ने बताया भारत का मिशन 2036

काशी ०४/०१ (संवाददाता): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का भव्य उद्घाटन किया। काशी के सांसद के रूप में खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए पीएम ने कहा कि यह टूर्नामेंट %एक भारत, श्रेष्ठ भारत% की सुंदर तस्वीर पेश कर रहा है, ज़्योंकि इसमें देश के 28 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं।

प्रधानमंत्री ने वॉलीबॉल के खेल को भारत की प्रगति से जोड़ते हुए एक खास संदेश दिया। उन्होंने कहा, %वॉलीबॉल संतुलन, सहयोग और इच्छाशक्ति का खेल है। जिस तरह वॉलीबॉल में जीत टीम के आपसी भरोसे और तालमेल पर निर्भर करती है, वैसे ही हमारा देश भी टीम भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। जब हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाता है, तभी राष्ट्र सफल होता है।%

पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि 2014 के बाद से भारत का खेल मॉडल पूरी तरह बदल चुका है। अब सरकार की नीतियां एथलीटों के कल्याण को प्राथमिकता देती हैं।

उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट और खेलो भारत नीति 2025 का जिक्र करते हुए कहा कि इन सुधारों से खेलों में पारदर्शिता आएगी और सही प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

संबोधन के दौरान पीएम ने भारत की भविष्य की खेल योजनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले दशक में भारत ने फीफा अंडर-17 और हॉकी वर्ल्ड कप जैसे 20 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट्स की सफल मेजबानी की है।

पीएम ने कहा, %भारत 2030 के कॉमनवेल्थ गेज़्स की मेजबानी करेगा और 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए सक्रिय रूप से दावेदारी की तैयारी कर रहा है।%

प्रधानमंत्री ने कहा कि काशी में तैयार हो रहे नए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर से यहां के युवाओं को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि काशी अब बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए पूरी तरह तैयार है, जिससे शहर की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है।

जवान ने चलती ट्रेन के आगे लेटकर दी जान, तलाश में जुटी पुलिस

विशाखापज़नम ०४/०१ (संवाददाता): आंध्र प्रदेश के विशाखापज़नम स्थित दुव्वाड़ा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां भारतीय सेना के एक सेवारत जवान ने प्लेटफार्म नंबर-1 पर आ रही चलती ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। मृतक की पहचान नीलमपु वेंकट रेड्डी के रूप में हुई है, जो विशाखा पज़नम के पेड़ागांटयाडा इलाके के रहने वाले थे। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या उन्हें रोक पाता, तेज रज़्तार ट्रेन उनके ऊपर से गुजर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। जवान ने जानबूझकर अपना सिर चलती ट्रेन के पहियों के नीचे रख दिया, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

20 साल बाद साथ आए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए जारी किया घोषणापत्र

मुंबई ०४/०१ (संवाददाता): राजनीति में दो दशक की कड़वाहट के बाद एक साथ आए उद्धव ठाकरे (शिवसेना यूबीटी) और राज ठाकरे (एमएनएस) ने शनिवार को मुंबई नगर निगम चुनाव के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया। इसे %वचन नामा% नाम दिया गया है। 15 जनवरी को होने वाले चुनावों के लिए दोनों भाइयों ने अपने गठबंधन को मराठी मानुष और मुंबई की रक्षा के लिए एक शिव-शक्ति के रूप में पेश किया है। स्वाभिमान निधि- घरेलू काम करने वाली महिलाओं और कोली (मछुआरा) महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।सस्ता भोजन-मीनाताई ठाकरे के नाम पर %मां साहेब% रसोई शुरू की जाएगी, जहां सिर्फ 10 रुपये में नाश्ता और दोपहर का खाना मिलेगा। प्रॉपर्टी टैज़्स में छूट-700 वर्ग फुट तक के घरों का संपज़ि कर माफ करने का प्रस्ताव है। सस्ता सफर-बेस्ट बसों का

न्यूनतम किराया 10 रुपये से घटाकर 5 रुपये किया जाएगा और नए रूट शुरू होंगे।शिक्षा-बीएमसी के स्कूलों (मुंबई पज़्लिक स्कूल) में अब नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई हो सकेगी। गिग वर्कर्स की मदद-डिलीवरी और अन्य काम करने वाले गिग वर्कर्स को ई-बाइक खरीदने के लिए 25,000 रुपये का ज़्याज मुक्त कर्ज दिया जाएगा। पार्किंग-पुनर्विकसित इमारतों में हर ज़्लैट के लिए एक पार्किंग स्लॉट अनिवार्य किया जाएगा। घोषणापत्र जारी करते हुए उद्धव और राज ठाकरे ने बीजेपी पर कड़ा प्रहार किया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया कि राज्य में लोकतंत्र खत्म हो गया है और अब वोट चोरी के बाद उमीदवारों की चोरी की जा रही है। उन्होंने मांग की कि जहां भी उज़्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं, वहां दोबारा चुनाव हों और अधिकारियों के कॉल रिकॉर्ड की जांच की जाए।वहीं, राज ठाकरे ने बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वे महाराष्ट्र को %यूपी-बिहार% बनाना चाहते हैं, जो राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई का अगला मेयर निश्चित रूप से एक मराठी ही होगा।

तृणमूल सरकार की उन्नयनेर पांचाली के मुकाबले में भाजपा का चोरदेर पांचाली अभियान-शुभेंदु अधिकारी

०४/०१ (संवाददाता): पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को कहा कि भाजपा तृणमूल कांग्रेस सरकार के कथित गलत कामों से लोगों को अवगत कराने के लिए पूर्व मेदिनीपुर ज़िले में 'चोरदेर पंचाली' नामक झांकियां निकालेगी। अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू किया गया उन्नयनेर पांचाली (विकास की गाथा) अभियान, नरेन्द्र मोदी नीत सरकार और राज्य में विपक्षी दलों के बारे में झूठ फैला रहा है।उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक रैली के दौरान पत्रकारों से कहा, ''भले ही लोग अब तृणमूल कांग्रेस के धोखे को समझ चुके हैं, फिर भी भाजपा को इस अभियान का मुकाबला करना होगा और लोगों को सच्चाई दिखानी होगी। कल से हम

नंदीग्राम समेत पूर्व मेदिनीपुर में चोरदेर पांचाली (चोरी की कहानियां) की झांकियां निकालेंगे।रैली को संबोधित करते हुए अधिकारी ने आरोप लगाया कि नंदीग्राम के हिंदू सज़ाधारी पार्टी द्वारा संरक्षित जिहादी तत्वों के भय में जी रहे हैं।

उन्होंने कहा, जब हिंदू एकजुट नहीं होते तो ज़्या होता है, यह सीमा पार बांग्लादेश में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।एक समय बांग्लादेश की जनसंज़्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत थी, लेकिन अब यह घटकर 7 प्रतिशत रह गई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा, अगर नंदीग्राम के हिंदू एकजुट नहीं होते हैं, तो अत्याचार और बढ़ेंगे।तृणमूल के प्रदेश महासचिव कुणाल घोष ने कहा कि अधिकारी सज़ा में आने के लिए ध्रुवीकरण का खतरनाक दांव खेल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया, बंगाल के लोग भाजपा की चाल में नहीं फंसेंगे, जो बांग्लादेश में हिंसा की घटनाओं का हवाला देकर यहां सांप्रदायिक कलह के बीज बो रही है।

बलूच नेता ने जयशंकर को लिखी चिट्ठी

इस्लामाबाद ०४/०१ (संवाददाता): पाकिस्तान और चीन के बीच गहराते गठजोड़ को लेकर एक सनसनीखेज दावा सामने आया है। जाने-माने बलूच नेता और मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने आशंका जताई है कि चीन अगले कुछ महीनों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में अपनी सेना तैनात कर सकता है। बलूच नेता ने अपने पत्र में न केवल चीनी हस्तक्षेप पर चिंता जताई, बल्कि साल 2025 में भारत द्वारा किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' की जमकर तारीफ भी की है। मीर यार बलूच ने कहा कि बीजिंग और इस्लामाबाद का गठबंधन बलूच जनता के लिए खतरे की घंटी है।

गोपालगंज पहुंचा दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, दर्शन के लिए उमड़े हजारों भक्त

०४/०१ (संवाददाता): तमिलनाडु के महाबलीपुरम से शुरू हुई एक ऐतिहासिक यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव के करीब है। दुनिया का सबसे विशाल शिवलिंग बिहार के गोपालगंज पहुंच चुका है, जहाँ इसके दर्शन के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है। 210 मीट्रिक टन वजनी और 33 फीट ऊंचे इस शिवलिंग को पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा।इस अद्भुत शिवलिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में

एक ही विशाल %ज़्लैक ग्रेनाइट% पत्थर (मोनोलिथ) को काटकर बनाया गया है। इसे तराशने में कलाकारों को करीब 10 साल का समय लगा।शिवलिंग की सतह पर 1008 छोटे सहस्त्रलिंगम भी उकेरे गए हैं, जो इसकी दिव्यता को और बढ़ाते हैं। इस भारी-भरकम शिवलिंग को 96 पहियों वाले एक विशेष ट्रक के जरिए सड़क मार्ग से बिहार लाया गया है।

गोपालगंज पहुंचते ही स्थानीय लोगों ने जयकारों के साथ शिवलिंग का स्वागत किया। स्थानीय निवासी सत्यम गोस्वामी ने खुशी जताते हुए कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे यहां आया है। सुबह से ही भक्त पूजा-अर्चना के लिए जुट रहे हैं। वहीं कुंदन देवी नाम की श्रद्धालु ने बताया कि पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल है और लोग दूर-दूर से इस विशाल शिवलिंग की एक झलक पाने आ रहे हैं। महावीर मंदिर न्यास समिति द्वारा बनवाए जा रहे इस भव्य मंदिर का निर्माण कार्य जोरों पर है। मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा।

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और शीतलहर का डबल अटैक, कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी, बहुत खराब हुई हवा

नई दिल्ली ०४/०१ (संवाददाता): दिल्ली-एनसीआर में कड़ाके की ठंड के साथ-साथ प्रदूषण का कहर जारी है। रविवार सुबह दिल्लीवासी ठंडी, बर्फीली हवाओं और घने कोहरे के बीच उठे। कोहरे के कारण शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई, जिससे यातायात पर भी असर पड़ा। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसत वायु गुणवज़ा सूचकांक 248 दर्ज किया गया, जो %खराब% श्रेणी में आता है। हालांकि, शहर के कई हॉटस्पॉट्स पर हालात इससे कहीं ज्यादा गंभीर बने हुए हैं।

राजधानी के मुज़्य मॉनिटरिंग स्टेशनों पर हवा की गुणवज़ा %बहुत खराब% श्रेणी में पहुंच गई है। आनंद विहार (350), रोहिणी (361), चांदनी चौक (355) और मुंडका (329) जैसे इलाकों में सांस लेना दूभर हो गया है। इसके विपरीत, ह्स्ड्डज्ञ द्वारका और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों में हवा थोड़ी बेहतर रही, जहां एज़्यूआई 177 दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि रविवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे ठिठुरन और बढ़ गई है।

प्रदूषण और स्मॉग की इस धुंध के बावजूद, इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां ज़ोर-शोर से जारी हैं। जवानों का अज़्यास और अन्य तैयारियां कोहरे के बीच भी थमी नहीं हैं। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 18 से 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। ठंड और धुंध का यह सिलसिला फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है।

वेनेजुएला को लेकर विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, भारतीयों को गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह

नई दिल्ली ०४/०१ (संवाददाता): विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शनिवार को भारतीय नागरिकों को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में हाल के घटनाक्रमों और वहां तेजी से बदलती स्थिति को देखते हुए सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह एडवाइजरी जारी की गई है।विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों से सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हालांकि, यह एडवाइजरी जारी करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया है। एडवाइजरी में कहा गया है, भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की सभी गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है।

विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला में पहले से मौजूद भारतीयों के लिए दिशानिर्देश भी जारी किए हैं, जिसमें उन्हें सतर्क रहने, अपनी गतिविधियों को सीमित रखने और कराकस में भारतीय दूतावास के साथ नियमित संपर्क में रहने की सलाह दी गई है।वेनेजुएला में हुए हालिया घटनाक्रमों के बाद बढ़े तनाव के बीच यह सलाह जारी की गई है।इससे पहले, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की थी कि वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हेलीकॉप्टर से वेनेजुएला से निकालकर कैरेबियन में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा में ले जाया गया था।ट्रंप ने फॉज़्स न्यूज को बताया, वे न्यूयॉर्क की ओर जा रहे होंगे, और कहा कि हेलीकॉप्टर उन्हें देश से बाहर ले गए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मादुरो सोमवार को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पहली बार पेश हो सकते हैं। अटॉर्नी जनरल पाम बोंडी ने कहा कि मादुरो और उनकी पत्नी पर न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में मादक पदार्थों से संबंधित अपराधों सहित कई आरोपों में पहले ही अभियोग लगाया जा चुका है।डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी कार्रवाई की वैधता पर सवाल उठाने वाली आलोचनाओं को खारिज कर दिया और वेनेजुएला के अधिकारियों को मादुरो के समर्थन में खड़े रहने वालों को चेतावनी दी। हालांकि, कई वरिष्ठ वेनेजुएला नेताओं ने इस ऑपरेशन की आलोचना की।

मिशन से परिचित लोगों के हवाले से आई रिपोर्टों में कहा गया है कि इस ऑपरेशन में अमेरिका की विशिष्ट इकाइयां शामिल थीं, जिन्हें सीआईए का समर्थन प्राप्त था और अमेरिकी सेना के डेल्टा फोर्स कर्मियों द्वारा इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। मादुरो को 2020 से ही अमेरिका में आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें वाशिंगटन ने उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों को वेनेजुएला के नेतृत्व की तरफ से नकारा गया है। ऐसे में विदेश मंत्रालय की यह एडवाइजरी वेनेजुएला में मौजूदा स्थिति और चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच भारतीयों सहित विदेशी नागरिकों के लिए संभावित खतरों से आगाह करती है।

विविध समाचार

परिवार के भीतर बातचीत से रुकेगा लव जिहाद’, बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत

नई दिल्ली ०४/०१ (संवाददाता): राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा है कि परिवार के भीतर मजबूत संवाद के जरिए लव जिहाद जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। उनका कहना था कि जब घर में खुलकर और नियमित बातचीत होती है, तो ऐसी समस्याएं अपने आप कम होने लगती हैं। भोपाल के शिवनेरी भवन में आयोजित ‘स्त्री शक्ति संवाद’ कार्यक्रम में उन्होंने यह विचार रखे। मोहन भागवत ने कहा कि समाज को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि किसी परिवार की बेटी किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में कैसे आ जाती है। उनके अनुसार, परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी और आपसी दूरी इस तरह की स्थितियों को जन्म देती है। उन्होंने कहा कि जब घर में निरंतर बातचीत का माहौल होता है, तो धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रति सज़्मान

स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।

संघ प्रमुख ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तीन अहम बिंदुओं पर जोर दिया। पहला, परिवार के भीतर निरंतर और सकारात्मक संवाद। दूसरा, लड़कियों में सजगता, आत्मविश्वास और आत्मरक्षा की भावना का विकास। तीसरा, इस तरह के अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ सज़्त और प्रभावी कार्रवाई। उन्होंने यह भी कहा कि सामाजिक संगठनों और पूरे समाज को सजग रहकर सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराना होगा, तभी इसका स्थायी समाधान संभव है। महिलाओं की भूमिका पर बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि किसी भी सज़्य समाज की पहचान महिलाओं की स्थिति से होती है। उनके अनुसार, भारतीय संस्कृति, धर्म और सामाजिक व्यवस्था महिलाओं के योगदान से ही सुरक्षित और सुदृढ़ बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वह दौर अब पीछे छूट चुका है जब महिलाओं को केवल सुरक्षा के नाम पर घर तक सीमित रखा जाता था। आज पुरुष और महिलाएं मिलकर परिवार और समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए दोनों का जागरण जरूरी है। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, अवसरों की समानता और वैचारिक चेतना को समय की मांग बताया। भागवत ने कहा कि यह प्रक्रिया पहले से चल रही है और महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इसे और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। लिंग भेदभाव और उत्पीड़न के संदर्भ में उन्होंने कहा कि जहां पश्चिमी समाज में विवाह के बाद महिला की पहचान तय होती थी, वहीं भारतीय परंपरा में मातृत्व के माध्यम से महिला को उच्च स्थान दिया गया है। उनके अनुसार, मातृत्व भारतीय मूल्यों का केंद्रीय तत्व है।

संघ प्रमुख ने आधुनिकता के नाम पर अंधे पश्चिमीकरण की प्रवृज़ि पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बचपन से बच्चों को कौन से संस्कार और मूल्य दिए जा रहे हैं, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सक्षम बनाना जरूरी है, ज़्योंकि भारतीय परंपराएं उन्हें सीमित नहीं करतीं, बल्कि सशक्त और विशिष्ट बनाती हैं। रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय महिलाओं ने हर युग में साहस और शक्ति का परिचय दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है और देश इस भूमिका के लिए स्वयं को तैयार कर रहा है। देश की लगभग आधी आबादी महिलाएं हैं और बड़ी संज़्या में महिलाएं समाज और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, हालांकि अभी भी कई महिलाएं इस प्रक्रिया से नहीं जुड़ पाई हैं।

उन्होंने कहा कि जहां महिलाओं का सज़्मान होता है और उन्हें सुरक्षित स्थान मिलता है, वहां समाज स्वाभाविक रूप से संतुलित और स्वस्थ रहता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आज समाज सांस्कृतिक आक्रमण जैसी नई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिन्हें सांस्कृतिक मार्क्सवाद और वोकिज्म जैसे नाम दिए जाते हैं। इनसे निपटने के लिए अपने धर्म, मूल्यों और परंपराओं को गहराई से समझना और आत्मसात करना जरूरी है।

कांग्रेस ने सरदार पटेल को इतिहास से मिटाने का बहुत प्रयास किया-नड्डा

नयी दिल्ली ०४/०१ (संवाददाता): भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने शनिवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरदार पटेल को इतिहास से मिटाने का बहुत प्रयास किया और यहां तक कि पार्टी ने नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा सरदार पटेल के स्मारक के रूप में निर्मित ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ की लागत और आवश्यकता पर भी सवाल उठाया।

नड्डा ने यहां अटलदरा गांव में ‘सरदार एट द रेट ऑफ150 यूनिटी मार्च’ के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सरदार पटेल को याद किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी नीतियों से कश्मीर मुद्दे को बिगड़ने दिया, जबकि सरदार पटेल ने आजादी के बाद 562 रियासतों का सफलता पूर्वक देश में विलय किया। नड्डा ने आरोप लगाया, ‘‘कांग्रेस ने एक षड्यंत्र के तहत जानबूझकर सरदार पटेल को इतिहास से मिटाने की बहुत कोशिश की। वे चाहते थे कि उनका नाम गायब हो जाए ताकि उन्हें याद न रखा जाए। लंबे समय तक, कांग्रेस ने यह सुनिश्चित करने के लिए काम किया कि भारत के लौह पुरुष का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज न हो।

नड्डा ने कहा कि सरदार पटेल का निधन 1950 में हुआ था, लेकिन उन्हें 1991 में ‘भारत रत्न’ से सज़्मानित किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल को सच्चे अर्थों में याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन, जब मोदी ने पटेल को श्रद्धांजलि स्वरूप गुजरात के नर्मदा जिले में दुनिया की सबसे ऊंची ‘स्टैच्यू ऑफ यूनिटी’ बनाने का फैसला किया, तो कांग्रेस ने इसकी लागत पर सवाल उठाए। नड्डा ने कहा, ‘‘कांग्रेस ने पूछा कि इतना पैसा ज़्यों खर्च किया जा रहा है। और जब सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई, तो कांग्रेस के सदस्यों ने सवाल उठाया कि इससे ज़्या हासिल होगा। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि सरदार पटेल ने 562 रियासतों का एकीकरण किया था, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने कहा था कि वह जज़्मू-कश्मीर पर फैसला लेंगे।

नित्यानंद राय का दावा, 2036 तक बुजुर्गों की आबादी बढ़कर 22.74 करोड़ हो जाएगी

नयी दिल्ली ०४/०१ (संवाददाता):केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को कहा कि अगले डेढ़ दशक में भारत की बुजुर्ग आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्रित कल्याणकारी उपायों की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित करता है। कांग्रेस सांसद चमाला किरण कुमार रेड्डी द्वारा लोकसभा में उठाए गए प्रश्न का उज़र देते हुए, नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंज़्या आयोग द्वारा गठित जनसंज़्या अनुमानों पर तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संज़्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 22.74 करोड़ होने की उज़्मीद है, और कहा कि इसी अवधि के दौरान कुल जनसंज़्या में उनकी हिस्सेदारी 8.4 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की आबादी में तेज वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और

डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां पेश करेगी। इन उभरती चिंताओं के जवाब में, राय ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय अटल वयो अज़्युदय योजना (अव्यय) को लागू कर रहा है, जो 1 अप्रैल, 2021 से संचालित एक व्यापक योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, अटल वयो अज़्युदय योजना (अव्यय) का मुज़्य उद्देश्य आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवज़ा में सुधार करना और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ)/पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई)/ स्थानीय निकायों और बड़े पैमाने पर समुदाय की क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करके उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना है। वृद्धजनों की जनसंज़्या में वृद्धि के कारण, वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में स्वास्थ्य, सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।

भारत-रूस के संबंधों पर किसी देश का वीटो नहीं, पुतिन की यात्रा से नाराज अमेरिका को जयशंकर की दो टूक

नयी दिल्ली ०४/०१ (संवाददाता): विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को उन सुझावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया दो दिवसीय भारत यात्रा भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को जटिल बनाएगी। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि कोई भी देश अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ नई दिल्ली के संबंधों को निर्देशित करने की उज़्मीद नहीं कर सकता। एचटी लीडरशिप समिट 2025 में बोलते हुए, विदेश मंत्री ने प्रमुख देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को बनाए रखने में भारत की स्वायज़ता का उल्लेख किया और कहा कि किसी भी अन्य देश द्वारा अन्य देशों के साथ नई दिल्ली के संबंधों को निर्देशित करना उचित प्रस्ताव नहीं है।

जयशंकर ने कहा कि मैं असहमत हूँ। सभी जानते हैं कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध हैं। और किसी भी देश के लिए यह अपेक्षा करना कि वह इस बात पर अपनी राय दे कि हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को कैसे विकसित करते हैं, एक उचित प्रस्ताव नहीं है, ज़्योंकि याद रखें, दूसरा भी यही उज़्मीद कर सकता है। उन्होंने इस मामले में भारत की पसंद की स्वतंत्रता की पुष्टि की और कहा कि अपनी रणनीतिक स्वायज़ता को बनाए रखने की उसकी नीति जारी है।विदेश मंत्री ने कहा कि हमने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि हमारे बीच बहुपक्षीय संबंध हैं, हमें चयन की स्वतंत्रता है और हम रणनीतिक स्वायज़ता की बात करते हैं, और यह जारी है, तथा मैं कल्पना नहीं कर सकती कि किसी को इसके विपरीत की अपेक्षा करने का कोई कारण ज़्यों होगा। जयशंकर ने देश के किसानों, श्रमिकों और छोटे व्यवसायों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में कड़ी बातचीत करने के नई दिल्ली के रुख को भी दोहराया।उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रज़्प के नेतृत्व वाले नए प्रशासन के बिल्कुल अलग दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया, लेकिन विश्वास व्यक्त किया कि एक संतुलित समझौता संभव है। जयशंकर ने कहा कि हर सरकार और हर अमेरिकी राष्ट्रपति का दुनिया से संपर्क करने का अपना तरीका होता है। मैं आपको यह बता सकता हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप के मामले में, यह उनके पूर्ववर्ती के तरीके से बिल्कुल अलग है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाते हुए भारत के प्रमुख आर्थिक हितों की रक्षा करने में अत्यंत विवेकपूर्ण कदम उठा रही है। आपको बस बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करनी है। हमारा मानना है कि हमारे अपने-अपने व्यापारिक हितों के लिए एक निर्णायक बिंदु हो सकता है, जिस पर कड़ी बातचीत की जाएगी -- ज़्योंकि अंततः मज़दूरों, किसानों, छोटे व्यवसायों और मध्यम वर्ग के हित ही मायने रखते हैं। जयशंकर ने कहा कि मैं असहमत हूँ। सभी जानते हैं कि भारत के दुनिया के सभी प्रमुख देशों के साथ संबंध हैं। और किसी भी देश के लिए यह अपेक्षा करना कि वह इस बात पर अपनी राय दे कि हम दूसरों के साथ अपने संबंधों को कैसे विकसित करते हैं, एक उचित प्रस्ताव नहीं है, ज़्योंकि याद रखें, दूसरा भी यही उज़्मीद कर सकता है।

उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रज़्प के नेतृत्व वाले नए प्रशासन के बिल्कुल अलग दृष्टिकोण को भी स्वीकार किया, लेकिन विश्वास व्यक्त किया कि एक संतुलित समझौता संभव है।

बिहार को टॉप 5 निवेश राज्य बनाने की तैयारी, नीतीश का बड़ा दांव, 50 लाख करोड़ की कार्ययोजना

पटना ०४/०१ (संवाददाता): बिहार में 10वीं बार मुज़्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार एज़्शन में हैं। रोजगार और उद्योग पर नीतीश सरकार का फोकस साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि उनकी सरकार बिहार में रोजगार और औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रही है।

अपने एज़्स पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य की तेज आर्थिक तरक्की और रोजगार पैदा करने के लिए वृहद पैमाने पर औद्योगीकरण का होना जरूरी है। बिहार सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है। औद्योगिक क्षेत्रों की संज़्या जो वर्ष 2005 में 46 थी, वह बढ़कर अब वर्ष 2025 में 94 हो गयी है।

सीएम ने कहा कि औद्योगिक इकाईयों की संज़्या वर्ष 2005 में 1674 थी, जो वर्ष 2025 में बढ़कर 3500 हो गयी है।

इसी प्रकार वर्ष 2005 में बिहार से औद्योगिक उत्पादों का निर्यात जो मात्र 25 करोड़ रूपये था, वह बढ़कर वर्ष 2025 में 17 हजार करोड़ रूपये हो गया है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की संज़्या 2005 के मुकाबले 72 हजार से बढ़कर 2025 में 35 लाख हो गयी है और बिहार के जी0एस0डी0पी0 में उद्योगां का योगदान वर्ष 2005 के 5.4 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 में 21 प्रतिशत से भी अधिक हो गया है। यह सरकार द्वारा बिहार के औद्योगिक विकास हेतु किये गये प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब बिहार को भारत के शीर्ष पांच निवेश

अनुकूल राज्यों में सज़्मिलित करने हेतु उद्योग विभाग देश-दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सज़्मेलनों का आयोजन करेगा, ताकि बड़े से बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। हमलोगों ने अगले 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश की कार्ययोजना पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत Ease of Doing Business (EoDB) को बढ़ावा देना, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिज़्स सुविधाओं के साथ 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, राज्य में 10 औद्योगिक पार्क एवं 100 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पार्कों को विकसित करना, उद्योग-प्रासंगिक कौशल एवं उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना एवं सभी जिलों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र स्थापित करना शामिल है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों के निर्यात एवं बाजार की सुविधा उपलज़्ध कराना प्रमुख है। मुज़्यमंत्री ने लिखा कि राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुज़्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल 44,073 उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि दी गयी है। इससे लोग अपना खुद का उद्योग/कारोबार कर रहे हैं और बड़ी संज़्या में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडज़्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी एवं फिनटेक सिटी की स्थापना हेतु कार्य योजना के निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन के सतत अनुश्रवण के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है। साथ ही बिहार को एक ‘वैश्विक-क्कुष्द्म द्गठ्ठस्त्र- ।।ह्वड्ड’ एवं ‘ग्लोबल वर्क प्लेस’ के रूप में विकसित एवं स्थापित करने हेतु कार्य योजना बनाकर उसके कार्यान्वयन के लिए सतत अनुश्रवण करने के लिए एक शीर्ष समिति का गठन किया गया है।

इसके अलावा प्रतिभाशाली युवाओं एवं उद्यमियों को राज्य अंतर्गत स्टार्टअप एवं अन्य न्यू एज इकोनॉमी प्रक्षेत्र के रोजगारोन्मुखी गतिविधियों को विस्तारित करने हेतु कार्य योजना बनाकर उसके कार्यान्वयन एवं सतत अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है।

सीएम ने कहा कि गयाजी के डोभी में लगभग 1,700 एकड़ में फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) की स्थापना प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है और जल्द ही उसका शुभारंभ भी कर दिया जाएगा।

कलिंग समाचार
THE KALINGA SAMACHAR
(A Hindi Daily News Paper)
PUBLISHED FROM ODISHA, JHARKHAND & CHATTISHGARH
FOR NEWS AND ADVERTISEMENT CONTACT
AT: QRS. NO. B/204, SECTOR-16
ROURKELA, PH. 0661-2646999
PRAKASH KUMAR DHAL (EDITOR)
E-mail: thekalingasamachar@gmail.com

विविध समाचार

इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर

बन कॅरियर को दें नई दिशा

आज के समय में इंटरनेट का इस्तेमाल तो सभी लोग करते हैं, लेकिन अगर सोच-समझकर इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाए। तो यह कमाई का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। हालांकि आपने भी देखा होगा कि आज के समय में बहुत से लोग सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के तौर खूब शोहरत हासिल कर रहे हैं। वहीं इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर बन लोग लाखों कमा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर के तौर पर अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर के तौर पर अपना कॅरियर बना शानदार कमाई कर सकते हैं। वर्तमान समय में अपनी नौकरी के साथ लोग सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी काफी अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अच्छी रीच और ज्यादा एक्टिव रहने वाले अकाउंट्स को ब्रांड प्रमोशन आदि को अच्छा खासा-पैसा मिलता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इंस्टाग्राम इंफ्लुएंसर के तौर पर आप अपने कॅरियर की शुरूआत कैसे करें।

टाइम मैनेजमेंट है जरूरी

जब भी आप नौकरी करते हैं, तो इसमें आपके काम करने का रूटीन फिक्स होता है। लेकिन जब बात सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की होती है, तो इसमें आपको अपने काम की सीमा खुद तय करनी होती है। फोन व लैपटॉप के जरिए आपको अपना काम करना होता है। ऐसे में आपको भी अपने काम की सीमा खुद तय करनी होगी। जिससे कि आप सोशल मीडिया के अलावा अन्य कामों को भी पर्याप्त समय दे सकें।

फिक्स्ड इनकम

जब आप कोई नौकरी करते हैं, तो हर महीने के आखिरी में आपके बैंक अकाउंट में एक फिक्स्ड इनकम आ जाती है। लेकिन बतौर सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर आपको कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं मिलती है। आपकी इनकम ब्रांड प्रमोशन आदि पर निर्भर करती है। इसलिए शुरूआत में आपको नौकरी के साथ इस काम को करना चाहिए। ताकि आपका खर्चा आसानी से चलता रहे। वहीं सोशल मीडिया पर हर इंफ्लुएंसर का एक-दूसरे से अलग होना जरूरी है। इसलिए आपको ओरिजिनल आइडिया पर काम करने के साथ एडिटिंग आदि भी सीखनी चाहिए।

पाइथन सीख कॅरियर को दें नई उड़ान

अगर आपको भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा सीखने में इंट्रेस्ट हैं, तो आप इस क्षेत्र में अपना कॅरियर बना सकते हैं। बता दें कि पाइथन सर्टिफिकेट कोर्स करने वाले छात्रों के सामने कई अच्छे कॅरियर ऑप्शन मौजूद होते हैं।

आज के समय में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग समय की जरूरत बन गया है। कंप्यूटर और उससे संबंधित कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स को आगे कई अच्छे कॅरियर विकल्प मौजूद है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बढ़ती मांग को देखते हुए आज के समय में लोग ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आप सभी ने पाइथन का नाम सुना ही होगा। पाइथन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक अहम हिस्सा है। पाइथन की जानकारी बढ़ाने के लिए लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का बेसिक सीखने के लिए सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हैं। जिसके जरिए उन्हे प्रोग्रामिंग की भाषा का ज्ञान मिलने के साथ ही कॅरियर के तौर पर भी अच्छे ऑप्शन मिलेंगे। जब भी कोई आपको सामने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या इससे संबंधित किसी भाषा में बात करेगा। तो आप बिना झिझके बड़ी आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको पाइथन कोर्स की जानकारी देने जा रहे है।

पाइथन सर्टिफिकेट कोर्स

- कोडिंग सीखने के इच्छुक उम्मीदवार इस कोर्स को कर सकते हैं।
- अगर आप भी प्रोग्रामिंग की भाषा में बेहतर बनना चाहते हैं, तो यह एक अच्छा कोर्स है।
- इस कोर्स को आप एक अच्छे भविष्य के लिए कर सकते है।

क्वालिफिकेशन

- कक्षा 10वी पास उम्मीदवार पाइथन सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं।
- आप बेसिक से उच्च स्तर के कोर्स की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

पाइथन सर्टिफिकेट कोर्स में क्या सिखाया जाएगा

- इस कोर्स में डेटा एनालिटिक्स का प्रयोग का समस्याओं का समाधान करना सिखाया जाएगा।
- इसके अलावा तमाम वेब एप्लिकेशन बनाना सिखाया जाएगा।
- सॉफ्टवेयर और वेबसाइट की कोडिंग सिखाई जाएगी।
- डाटा सुरक्षा सुनिश्चित करना सिखाया जाएगा।
- डाटा एल्गोरिदम को सु-व्यवस्थित करना सिखाया जाएगा।

बेहतर करियर अवसरों की तलाश में हैं बने इन्वेस्टमेंट बैंकर

ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन से पहले अक्सर विद्यार्थियों में कंफ्यूजन होता है कि वे अपनी रुचि से मैच करता हुआ कौन-सा कोर्स चुनें। जिन उम्मीदवारों की रुचि बैंकिंग या इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में होती है, वे इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में करियर बनाने पर विचार कर सकते हैं।

अगर आप उम्दा पर्किंग इन्वायर्नमेंट, आकर्षक सैलरी पैकेज और बेहतर करियर अवसरों की तलाश में है, तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर आपके लिए आदर्श हो सकता है। जानते हैं इस बूमिंग करियर के बारे में।

इन्वेस्टमेंट बैंकर जिस संस्थान या कंपनी के लिए काम करता है, उसे वहां के वित्तीय पहलुओं से जुड़ी ड्यूटीज को हैंडल करना होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर किसी कंपनी की कैपिटल, फंड्स, लोन, स्टॉक्स के साथ डील करते हैं। इन्हें कंपनी के क्लाइंट्स को लोन प्राप्त करने और इन्वेस्टमेंट करने के लिए सहयोग भी करना होता है।

कैसा होता है करियर?

किसी भी प्राइवेट या सरकारी संस्था में इन्वेस्टमेंट बैंकर की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसे संस्थान के आर्थिक लेनदेन से जुड़े रेकॉर्ड्स का मेंटेनेंस, मॉडिफिकेशन, टेस्टिंग और डेवलपमेंट करना होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की मांग हर संस्थान में होती है और इनका करियर भी काफी आकर्षक माना जाता है।

क्या होती हैं जिम्मेदारियां?

- विभिन्न मेथडोलॉजीस का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूएशन एनालिसिस करना।
- विभिन्न कैपिटल स्ट्रक्चर्स और पोटेंशियल ट्रान्सेक्शंस को एनालाइज करना।
- फाइनेंशियल मॉडल्स बिल्ड करना।
- क्लाइंट मीटिंग्स के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करना, जिसमें कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज जैसे विषय कवर होते हों।
- न अपने टीम मेंबर्स के साथ डील करना।

कौन-सी स्किल्स जरूरी?

- टेक्निकल स्किल्स
- प्रेशर में काम को हैंडल करना
- अच्छी मैथमैटिकल और कैलकुलेशन स्किल्स
- फाइनेंशियल स्किल्स में पूरी तरह से परफेक्टहोना
- बिजनेस को विकसित करने के लिए नए अवसर उत्पन्न करना और उनकी पहचान करना।

सैलरी और करियर स्कोप

जिनके पास इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में बैचलर की डिग्री होती है, उनका असिस्टेंट या जूनियर एनालिस्ट की पोजिशन पर वार्षिक सैलरी पैकेज सात से आठ लाख तक का होता है। बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में ऐसे ही स्किल्ड और प्रतिभाशाली बैंकर्स की जरूरत है, जो संस्थान की ग्रोथ में योगदान कर सकें। इसलिए इस फील्ड में करियर को आगे बढ़ाने का काफी स्कोप है।

दिलकश आवाज और शानदार भाषाई कौशल के दम पर बनें वॉइस ओवर आर्टिस्ट

वॉइस ओवर आर्टिस्ट या डबिंग आर्टिस्ट बनने के लिए किसी विशेष क्वॉलिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। दिलकश आवाज और शानदार भाषाई कौशल के दम पर कोई भी इस क्षेत्र में आ सकता है। वैसे हाल ही में कुछ ऐसे कोर्स भी शुरू हुए हैं, जो डबिंग आर्टिस्ट की प्रतिभा को संवारने में मदद करते हैं। इनमें प्रवेश के लिए 10वी पास होना जरूरी है।

योग्यता

किसी डबिंग आर्टिस्ट के लिए पहली जरूरत तो इसी बात की है कि उसकी आवाज अच्छी हो और भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ हो। आप चाहे फिल्मों, विज्ञापनों के लिए डबिंग कर रहे हो या फिर रेडियो, टीवी के लिए अपनी आवाज दे रहे हो, आपकी आवाज 'ब्रॉडकास्ट क्वॉलिटी' की होनी चाहिए। आवाज की गुणवत्ता तो प्रकृति देती है लेकिन वॉइस मॉड्यूलेशन आपको सीखना होगा। आखिर आवाज का सही उतार-चढ़ाव ही तो डबिंग की जान है! साथ ही आपका गला साफ होना चाहिए और उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट। यदि आप डबिंग आर्टिस्ट के रूप में करियर बनाना चाहते है, तो मॉक डबिंग प्रेक्टिस करते रहें। साथ ही अपने भाषाई हुनर को भी मांजते रहें। जिस तरह अभिनेता अलग-अलग लोगों के हाव-भाव का बारीकी से अध्ययन करता है, उसी तरह डबिंग आर्टिस्ट को अलग-अलग लोगों के बोलने के अंदाज का अध्ययन करते रहना चाहिए। ध्यान रहे, डबिंग आर्टिस्ट के रूप में आपको विभिन्न किरदारों की आवाज बनना होगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलें-जुलें, उनसे 'कनेक्ट' करें।

अवसर

डबिंग आर्टिस्ट के लिए आज अवसरों की तो कोई कमी ही नहीं है। विभिन्न रेडियो तथा टीवी चैनलों, प्रोडक्शन हाउसेज, विज्ञापन उद्योग, डॉक्यूमेंटरी फिल्मस, एनिमेशन जगत, ऑनलाइन एजुकेशन (ऑडियो बुक डबिंग) आदि में वॉइस-ओवर आर्टिस्ट्स की भारी मांग है। इस फील्ड में शुरूआत में स्ट्रगल तो करना पड़ता है लेकिन एक बार इंडस्ट्री में आपकी आवाज की पहचान बन जाए, तो फिर कमाई कई गुना बढ़ती जाती है। डबिंग आर्टिस्ट को आम लोगों के बीच अभिनेताओं जैसी शोहरत तो नहीं मिलती लेकिन मनोरंजन जगत के भीतर प्रतिभाशाली आर्टिस्ट्स का खासा नाम होता है।

कोर्स

इस क्षेत्र में कोई डिग्री या डिप्लोमा कोर्स नहीं होता। हां, कुछ संस्थाएं इसके सर्टिफिकेट कोर्स संचालित करती हैं, जिनकी अवधि एक महीना होती है।

इन क्षेत्रों में महिलाओं के लिए बेहतरीन कॅरियर ऑप्शन

महिलाओं ने किचन से केबिन तक का रास्ता तय करने में अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है। खेतों में काम करने से लेकर आसमान में हवाई जहाज उड़ाने तक का काम महिलाए कर ली हैं। महिलाए हर क्षेत्र में अपना नाम बना रही हैं। पुराने भारत से लेकर नए भारत तक की महिलाओं की तस्वीर दिन प्रति दिन बदलती जा रही है।

एक समय तक महिलाओं को घर की चारदीवारी के लिए बेहतर माना जाता था। लेकिन अब महिलाएं घर की दहलीज पार कर काम करने लगी हैं। महिलाओं ने किचन से केबिन तक का रास्ता तय कर लिया है। खेतों में काम करने से लेकर आसमान में हवाई जहाज उड़ाने तक का काम महिलाए कर ली हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में अपना नाम बना रही है।

इतना ही नहीं हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी योग्यता का भी बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर महिलाएं अपना बेहतर कॅरियर बना सकती हैं। यह टॉप 3 फील्ड महिलाओं को बेहतरीन कॅरियर के साथ स्मार्ट सैलरी भी देगी।

टीचिंग

महिलाओं के लिए टीचिंग हमेशा से ही बेस्ट कॅरियर रहा है। इस प्रोफेशन में जाने के लिए परिवार का भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। टीचिंग फील्ड में अच्छा पैसा होने के साथ ही रुतबा भी है। इस क्षेत्र में कॅरियर बना कर आप लोगों की जिंदगी में अहम रोल निभा सकती है। हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है। इस जॉब के साथ समय भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। एक दशक से इस फील्ड में नौकरी के अवसर भी बढ़े हैं। प्राइमरी हो या डिग्री हर जगह अच्छी सैलरी मिलती है। इस फील्ड में आपको 55,000 से 2,25,000 रुपए तक प्रतिमाह पा सकती है।

न्यूट्रिशन या फिटनेस

आज के समय में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरुकता बढ़ी है। हर कोई फिट और सेहतमंद रहना चाहती है। इस क्षेत्र में कॅरियर की अपार संभावनाए है। अगर आप योग, न्यूट्रिशन व एक्सरसाइज एक्सपर्ट्स हैं। तो इस फील्ड में अपना शानदार कॅरियर बना सकती है। आप इसकी शुरूआत डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भी कर सकती हैं। इस फील्ड में महिलाएं साल भर में 3-4 लाख रुपए सालाना कमा सकती है।

ह्यूमन रिसोर्स

कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी की चाह रखने वाली महिलाओं के लिए यह क्षेत्र काफी अच्छा है। आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में MBA या PGDM करने के बाद इस फील्ड में नौकरी कर सकती है। जो महिलाए लोगों की समस्या को सॉल्व करने करने में दिलचस्पी रखती है। यह जॉब उनके लिए बेस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू करना, उन्हे ट्रेड करना, सैलरी, विश्लेषण, पॉलिसी बनाना साथ ही साथी कर्मियों की देखभाल करना होता है। इस फील्ड में 3-4 लाख रुपए साला कमा सकती हैं। वहीं एक्सपीरियंस के बाद सैलरी भी बढ़ती जाती है।

कलिंग समाचार

संपादकीय

सोमवार 05 जनवरी 2026

देश में ध्रुवीकरण की कोशिशें तेज

बिहार चुनाव जीतने के बाद अब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प.बंगाल और असम जैसे चुनावी राज्यों में सक्रिय हो गए हैं। बीते दो दिनों में उनकी दो सभाएं प.बंगाल और असम में हुईं। प.बंगाल के नादिया जिले में उनका हेलीकॉप्टर धुंध की वजह से न उतर सका तो उन्होंने कोलकाता से ही वर्चुअली सभा को संबोधित किया, जिसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करने पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नादिया में उनके खिलाफ पोस्टर और बैनर लगे थे, जिसके बाद सवाल उठता है कि क्या श्री मोदी विरोध का सामना करने से डर गए और इसलिए धुंध को लौटने का कारण बताया जा रहा है। क्योंकि पंजाब चुनाव के वक्त वे किसानों के विरोध की वजह से बीच रास्ते से लौट आए थे और तब उन्होंने कहा था कि अपने मु यमंत्री से कहना मैं जिंदा वापस लौट आया। लोकतांत्रिक देश में जनता के विरोध को जान पर खतरे की तरह दिखाना यह बताता है कि प्रधानमंत्री को लोकतंत्र में जनता को मिले अधिकार सुहाते नहीं हैं। खैर, ठंड का मौसम बीतेगा और धुंध खत्म होगी, तब तो नरेन्द्र मोदी को बंगाल में प्रचार के लिए जाना ही होगा, तब अगर विरोध होता है, तो कितनी बार वे लौटेंगे, ये देखना होगा। प.बंगाल में नरेन्द्र मोदी असम गए और वहां उन्होंने इतिहास की गलत बयानी कर पं.नेहरू और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। लेकिन इस कोशिश में श्री मोदी ने खुद को उपहास का पात्र बना दिया है कि आखिर कब तक वे इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करेंगे। दरअसल श्री मोदी ने 20 दिसंबर को गुवाहाटी में आरोप लगाया कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पहले ही इस जगह की पहचान मिटाने की साजिश रची थी, जब मुस्लिम लीग और ब्रिटिश ताकतें मिलकर भारत को बांटने की जमीन तैयार कर रही थीं, उस समय असम को भी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की योजना थी। कांग्रेस भी उस साजिश का हिस्सा बनने वाली थी। तब बोरदोलोई जी ने अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े होकर असम की पहचान मिटाने की इस कोशिश का विरोध किया और असम को देश से अलग होने से बचाया।लेकिन हकीकत यह है कि मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय राजनीतिक नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए तीन ब्रिटिश कैबिनेट सदस्यों का एक प्रतिनिधिमंडल भेजा था, जिसमें ब्रिटिश भारत के लिए तीन स्तरीय प्रशासनिक संरचना का प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें शीर्ष स्तर पर संघीय संघ, निचले स्तर पर अलग-अलग प्रांत और मध्य स्तर पर प्रांतों के समूह थे। उत्तर-पश्चिम भारत, पूर्वी भारत और भारत के शेष मध्य भागों के लिए समूह ए, बी और सी नामक तीन समूहों का प्रस्ताव रखा गया था। समूह ए में हिंदू बहुल प्रांत (जैसे बॉ बे, मद्रास, यूपी) थे, समूह बी में मुस्लिम बहुल प्रांत (पंजाब, सिंध, उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत) थे और समूह सी में बंगाल और असम, जिसमें बंगाल मुस्लिम बहुल था, जबकि असम हिंदू बहुल। मुस्लिम लीग चाहती थी कि पूरा समूह सी पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं थी। न ही कांग्रेस ये चाहती थी कि असम को बंगाल के साथ मिलाया जाए। 29 दिसंबर 1946 के हरिजन अखबार में गांधीजी की असम को सलाह शीर्षक से प्रकाशित लेख में इसका स्पष्ट उल्लेख है। नेहरू भी असम को पाकिस्तान या बंगाल के साथ मिलाने के खिलाफ थे। 22 जुलाई 1946 को गोपीनाथ बोरदोलोई को पत्र में नेहरूजी ने लिखा, %समूह के खिलाफ फैसला करना सही और उचित था।% इसके बाद 23 सितंबर 1946 को लिखा, %किसी भी हालत में हम असम जैसे प्रांत को उसकी इच्छा के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करने पर सहमत नहीं होंगे। अप्रैल 1946 में बीबीसी को दिए इंटरव्यू में पं. नेहरू ने कहा, उत्तर-पश्चिम सीमा प्रांत में मुस्लिम बहुल होने के बावजूद लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया... असम भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के खिलाफ है। कांग्रेस के जबरदस्त विरोध के बाद अंग्रेजों ने असम को पाकिस्तान में मिलाने की योजना को रद्द कर दिया। कैबिनेट मिशन प्लान को कांग्रेस ने पूरी तरह नाकाम कर दिया। नेहरू के 10 जुलाई 1946 के प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस की स्पष्ट अस्वीकृति और असहमति माना गया।

राम के नाम पर रोज़गार गारंटी का राम नाम सत्य

गौरव जायसवाल

मनरेगा में काम की मांग ज़मीन से आती थी, लेकिन %वी बी जी राम जी% के इस नए कानून में केन्द्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना आबंटन होना है। अब एक प्रश्न यह है कि दिल्ली में बैठा बाबू कैसे तय करेगा कि राजस्थान में कितने वॉटर शेड बनने हैं या मध्यप्रदेश में कितने तालाब! यानी मूल तौर पर ये नया कानून कहता है कि अब बजट केन्द्र सरकार आधा ही देगी लेकिन फ़ैसले सारे दिल्ली में होंगे।

भारत सरकार द्वारा संसद में मनरेगा को हटाकर, %वी बी-जी राम जी% नाम से नया रोज़गार कानून लाया गया है। जल्दबाजी में किये गये इस बदलाव पर संसद में विपक्ष द्वारा की गई बहस भी मनरेगा जैसे व्यापक कार्यक्रम के संदर्भ से बहुत ही कमज़ोर रही। जिससे ये ज़ाहिर होता है कि आज सत्ता के साथ विपक्ष में बैठे जनप्रतिनिधि भी ज़मीनी हक़ीक़त से कितने दूर हैं। जो बहस ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था, सामाजिकता और राजनीति पर हो सकती थी वह महात्मा गांधी के नाम को हटाने पर सीमित होकर रह गई। आने वाले समय में इसका खामियाजा देश के मज़दूरों को उठाना होगा।

दो दशकों के बाद हुए इस बदलाव के मद्देनजर ज़रूरी है कि एक बार मनरेगा के पूरे सफ़र को समझने की कोशिश की जाये और ये भी समझने की कोशिश की जाये कि नये कानून से क्या बदलेगा और कैसे बदलेगा। दरअसल, 2005 में मनरेगा एक कानून की तरह लाया गया। देखने में यह एक सरकारी योजना जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे की बड़ी सोच यह थी कि योजना के छोटे दायरे में रखने के बजाय इसे कानून बनाया जाये और इस तरह देश के हर ग्रामीण नागरिक को रोज़गार का कानूनन अधिकार इस बिल ने दिया। सरकारी योजना एक तरह से सरकारी कृपा की तरह लोगों तक पहुंचती है लेकिन मनरेगा अधिकार के रूप में लोगों तक पहुंचा। इसीलिए इसे रोज़गार सृजन कार्यक्रम की तरह न देखते हुए देश के हर ग्रामीण नागरिक के सशक्तिकरण के कदम की तरह देखा जाना चाहिये। यही कारण है कि इसे हटाने के लिए भी सरकार को आज संसद में इतना ज़ोर लगाना पड़ रहा है।

इससे पहले की ये समझा जाये के मनरेगा से क्या हुआ, पहले इस अंतर को समझते हैं कि मनरेगा कैसे संसद में पास हुआ था और %वी बी जी राम जी% कैसे पास हुआ है! मनरेगा कानून का प्रारूप बनने से पहले 2003-04 में देश के कई ग्रामीण इलाकों में मज़दूर संगठनों द्वारा ऐसे एक कानून की मांग की मुहिम शुरू हुई, हालांकि ये मांग नई नहीं थी लेकिन पहली बार एक निर्णायक मांग की तरह जगह-जगह सामाजिक कार्यर्ताओं और मज़दूर संगठनों ने ऐसे कानून की तैयारी शुरू की। जिसके नतीज़तन जनांदोलनों द्वारा बनाए गए पहले प्रारूप को 2004 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद में प्रस्तुत किया गया, जहां इस पर पहली चर्चा हुई। फिर वहां से बिल प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचा, वहां से ग्रामीण विकास मंत्रालय और फिर लोकसभा में पेश हुआ। लोकसभा में आने के बाद मनरेगा का ये विधेयक संसद की स्थायी समिति में गया जहां फिर इसमें कई संशोधन किये गये।यहां गौरतलब बात ये है कि तब इस समिति के मुखिया भाजपा सांसद कल्याण सिंह हुआ करते थे। समिति से आने के बाद सारे संशोधनों को शामिल करते हुए 2005 में जब ये कानून संसद से पास हुआ तो पूर्ण सर्वस मति से सभी दलों ने इसका समर्थन किया था। वहीं %वी बी जी राम जी% के मामले में दिल्ली में बैठे अफ़सरों द्वारा तैयार प्रारूप को संसद के पटल पर रख दिया गया। जनता से राय-सुझाव मांगना तो दूर की बात है, यह प्रारूप स्थायी समिति को भी न भेजकर, विपक्ष के विरोध और नारेबाज़ी के बीच ध्वनि मत से पारित करवा दिया गया। जिन राज्य सरकारों से इसके अनुपालन में बजट की हिस्सेदारी अपेक्षित है उन तक से कोई संवाद नहीं किया गया। यानी एक तरफ मनरेगा ज़मीनी आवाज़ के तौर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से होकर संसद पहुंचा था वहीं %वी बी जी राम जी% मुट्ठी भर अफसरों का कारनामा है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर देश में लागू कर दिया गया है। अब देखते हैं कि पिछले बीस सालों में मनरेगा से क्या देश को कोई फ़ायदा हुआ? 2005 में जब मनरेगा लागू हुआ, ये इतना व्यापक कानून था कि पूरे देश मे लागू होने में ही इसे लगभग तीन साल लगे। पहले वर्ष में जब ये नरेगा हुआ करता था तब बजट में 11.3 हज़ार करोड़ का पहला आबंटन हुआ। वहीं पिछले वित्तीय वर्ष में मनरेगा में 86 हज़ार करोड़ का आबंटन हुआ। इन पिछले बीस वर्षों में कुल लगभग साढ़े 10 लाख करोड़ रुपये अलग-अलग सरकारों द्वारा मनरेगा को आवंटित किये गये। इस साढ़े 10 लाख करोड़ से क्या हुआ- इसे यदि सतही तौर पर समझा जाये तो ग्रामीण क्षेत्रों में कई तालाब, ट्रेंच, वॉटर शेड, सड़क, शौचालय जैसे निर्माण कार्य हुए और इस प्रक्रिया में मज़दूरों को काम मिला। काम मिलने से संभवत: पलायन भी कम हुआ होगा। लेकिन मनरेगा जैसे व्यापक विचार को सिर्फ रोज़गार सृजन के कार्यक्रम की तरह देखना ही सबसे बड़ी चूक होगी। इसे एक आर्थिक नीति की तरह देखा जाना चाहिये जिसने ज़मीन पर कुछ सामाजिक और राजनैतिक प्रभाव भी पैदा किये। पहला तो यह कि जो विशाल धनराशि मनरेगा में खर्च हुई, वह केंद्र सरकार की तिजोरी से सीधे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पहुंची, जिससे पिछले बीस वर्षों में भारत के गांवों में विकसित हो रहे बाज़ार को बड़ी बहुत बड़ी मदद मिली। मज़दूर के पास आए पैसे की विशेषता यह होती है कि वह रुकता नहीं है, सीधे बाज़ार में आता है और इसीलिए मनरेगा में खर्च हुए इस पैसे ने गांव-गांव में कपड़े, राशन किराना, हार्डवेयर, मोबाइल फोन जैसे व्यापार को बढ़ाया। आज गांवों कस्बों में जो हम ये दुकानें देखते हैं, उसमें मनरेगा के इस साढ़े 10 लाख करोड़ की बड़ी भूमिका है।

दूसरा बड़ा काम यह हुआ कि जैसे-जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पैसा बढ़ा, देश के गांव भी बड़े बाज़ार का हिस्सा होते गए। एक उदाहरण के तौर पर महिन्द्रा, फ़ोर्स मोटर्स, बजाज मोटर्स, हीरो जैसी बड़ी कंपनियां- जो बोलेरो, मार्शल, ट्रैक्स, तूफ़ान जैसे एसयूवी के मॉडल ग्रामीण भारत को ध्यान में रखकर बाज़ार में लाई, उनमें ब पर सेल मिली। वहीं बजाज, हीरो और टीवीएस जैसी कंपनियों ने कम कीमत की मोटर साइकिलों की ज़ोरदार बिक्री गांवों में की। आज यही कंपनियां भारत में बनी अपनी गाड़ियां विदेशों को निर्यात करने लगी हैं जिससे देश की जीडीपी बढ़ती है और सरकार बढ़ती अर्थव्यवस्था के आंकड़े दिखा पाती है। इस वृद्धि का एक बड़ा हिस्सा मनरेगा का यही बजट था।तीसरा एक बड़ा काम यह हुआ कि ग्राम पंचायत एक संस्था के रूप में और सशक्त हुई। ग्राम पंचायतों को रोज़गार सहायक के रूप में एक सहयोगी मिला। आम नागरिकों और ग्राम पंचायतों के बीच संपर्क, संवाद और निर्भरता बढ़ी, जो ग्राम स्वराज की दिशा में बड़ा कदम रहा।चौथा, लगभग सभी बड़े राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है, वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में आरक्षण भी है जो इस व्यवस्था में हाशिये के समुदायों को प्रतिनिधित्व का मौका देता है। मनरेगा ने त्रिस्तरीय व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधियों को जिनमें बड़ी सं या में महिलाएं और अनुसूचित जाति-जनजाति से आने वाले लोग हैं उन्हें पद के साथ आर्थिक निर्णय लेने की ताक़त दी। जिससे इन समुदायों से सक्षम नेतृत्व निकलने के रास्ते खुले। पांचवा, मनरेगा की व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए दो बड़ी बातें थीं एक था- सोशल ऑडिट, जो ग्रामीण नागरिकों को मनरेगा के अंतर्गत हुए कामों का पूरा हिसाब मांगने की ताक़त देता था। दूसरा, आज सरकार नये बिल में टेक्नालॉजी की दलील दी रही है, लेकिन मनरेगा का सूचना प्रबंधन तंत्र 2005 में ही इतना सक्षम था कि देश के हर गांव के हर मज़दूर को हुए भुगतान से लेकर काम की सारी वित्तीय जानकारी वेबसाइट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध थी, जिसके लिए देश के किसी भी नागरिक को सूचना के अधिकार के तहत न कोई जानकारी मांगने की ज़रूरत थी, न किसी लॉग इन आईडी और पासवर्ड की।

हमारे संविधान की प्रस्तावना न्याय के संवैधानिक मूल्य के अंतर्गत जिन तीन तरह के न्याय की बात करती है- सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय, मनरेगा असल में इन तीनों पैमानों में देश के सबसे हाशिये के समुदायों को सशक्त करने की ओर एक कदम था। ऐसा नहीं है, कि मनरेगा में कोई समस्या नहीं थी। बीस वर्षों बाद समीक्षा और सुधार की बड़ी गुंजाइश भी बनी, लेकिन सरकार ने सुधार करने की जगह इसे बंद कर नया कानून लाना चुना है। अब बात करते हैं नए कानून की। %वी बी जी राम जी% नाम की इस नई व्यवस्था को सरकार जितने गुपचुप तरीके से लाई है, पहले तो यही बात आम नागरिकों के मन में संदेह पैदा करने पर्याप्त है। फिर भी बिंदुवार इसके दो आवश्यक पहलुओं को समझते हैं। इस नए कानून में एक सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अब इसके क्रियान्वयन के लिए 40प्रतिशत तक का बजट राज्य सरकारों को देना है। अब इस समय जहां लाड़ली बहना योजना जैसे कार्यक्रमों के चलते राज्य सरकारें भयंकर वित्तीय दबाव से गुज़र रही हैं, बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में क्या राज्य सरकारें धीरे-धीरे मांग कम दिखाते हुए रोज़गार सृजन के काम कम नहीं कर देंगी? दूसरा आज भी जो राज्य राजनैतिक द्वेष के चलते केंद्र सरकार से जीएसटी के अपने हिस्से के लिए संघर्ष करते नज़र आते हैं। इनमें बंगाल जैसे राज्य भी हैं जहां रोज़गार सृजन की आवश्यकता अधिक है। इसलिए इन राज्यों के मन में भी अब बड़ा संशय है।

मनरेगा में काम की मांग ज़मीन से आती थी, लेकिन %वी बी जी राम जी% के इस नए कानून में केन्द्र सरकार तय करेगी कि किस राज्य को कितना आबंटन होना है। अब एक प्रश्न यह है कि दिल्ली में बैठा बाबू कैसे तय करेगा कि राजस्थान में कितने वॉटर शेड बनने हैं या मध्यप्रदेश में कितने तालाब! यानी मूल तौर पर ये नया कानून कहता है कि अब बजट केन्द्र सरकार आधा ही देगी लेकिन फ़ैसले सारे दिल्ली में होंगे।महात्मा गांधी गुलाम भारत में कहते थे कि %मैं सत्ता की ताक़त दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों से छीन कर देश के छह लाख गांवों में बांट देना चाहता हूं% मनरेगा इसी सपने की ओर बढ़ा आज़ाद भारत का एक सुंदर कदम था जिसे अब उस नये क़ानून ने पलट दिया है। और ये नया कानून गांव के मज़दूर, व्यापारी, पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम सचिव, रोजगार सहायक की शक्तियां छीन कर प्रधानमंत्री को देने की नीयत का लगता है।

एशियाई देशों के बीच सद्भाव सुनिश्चित करने में मददगार हो सकते हैं रूसी राष्ट्रपति

डॉ. अरुण मित्रा

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम)की संस्थापक आवाज़ के रूप में, दुनिया भारत से उ मीद करती है कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण, छोटे हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने और स्थायी शांति को बढ़ावा देना जारी रखेगा, खासकर हमारे अपने क्षेत्रीय दायरे में। इस भूमिका को निभाने के लिए, भारत को एक सूक्ष्म और कुशल कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा और उनका गर्मजोशी से स्वागत एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि जवाहर लाल नेहरू की भरोसेमंद भारत-रूस दोस्ती की विरासत आज भी कायम है। हालांकि आज का रूसी संघ पूर्व सोवियत संघ नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि रूस पूर्व सोवियत संघ का सबसे महत्वपूर्ण घटक था, और उस विरासत के कई तत्व आज भी मौजूद हैं। जैसा कि टैलीन में इंटरनेशनल सेंटर फॉर डिफेंस एंड सिक्योरिटी के रिसर्च फेलो इवान यू. क्लिश ने 6 दिसंबर 2025 को द टाइ स ऑफ इंडिया में छपे अपने एक लेख में लिखा था, %सोवियत युग की राजनीतिक और रणनीतिक विरासतें क्रेमलिन की सोच को आकार देना जारी रखे हुए हैं।%

दूसरे विश्व युद्ध के बाद उभरी द्विध्रुवीय व्यवस्था से लेकर 1990 के दशक की एकध्रुवीय दुनिया तक, और अब तेजी से बहुध्रुवीय होते माहौल तक, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में नाटकीय बदलाव आए हैं। आज, दुनिया के तीन प्रमुख शक्ति केंद्र-चीन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका - मजबूत अर्थव्यवस्थाओं, उन्नत सेनाओं और वैश्विक प्रभाव के मालिक हैं। भारत, अपनी बड़ी आबादी और बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ, एक उभरती हुई शक्ति बना हुआ है, लेकिन अभी भी नि न मध्यम-आय वर्ग से आगे बढ़ने के संक्रमण काल से गुजर रहा है। हालांकि एक बड़ा बाजार होने के बावजूद, वैश्विक भू-राजनीति को निर्णायक रूप से आकार देने से पहले हमें अभी काफी लंबा रास्ता तय करना है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नैम)की संस्थापक आवाज़ के रूप में, दुनिया भारत से उ मीद करती है कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण, छोटे हथियारों के प्रसार पर रोक लगाने और स्थायी शांति को बढ़ावा देना जारी रखेगा, खासकर हमारे अपने क्षेत्रीय दायरे में। इस भूमिका को निभाने के लिए, भारत को एक सूक्ष्म और कुशल कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा। उत्साहजनक रूप से, वर्तमान भारतीय नेतृत्व ने यह पहचानना शुरू कर दिया है कि भू-राजनीतिक संबंध वैचारिक समानता के बजाय आपसी हितों से निर्देशित होते हैं।

रूस ने दिसंबर 1998 में तत्कालीन प्रधान मंत्री येवगेनी प्रिमाकोव के माध्यम से रूस-भारत-चीन (आरआईसी) रणनीतिक त्रिकोण का प्रस्ताव रखा था, जिसकी कल्पना अमेरिकी एकध्रुवीय प्रभुत्व के प्रतिकार के रूप में की गई थी। उस समय भारत ने सीमित उत्साह दिखाया था। हालांकि, बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के कारण ब्रिक्स का उदय हुआ। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक अर्थशास्त्री ने ब्राजील, रूस, भारत और चीन के लिए ब्रिक्स शब्द को गढ़ा था ताकि चारों देशों की गतिशीलता में वृद्धि को दिखाया जा सके, जो बाद में ब्रिक्स समूह के रूप में एक वैश्विक राजनीतिक पहल के रूप में विकसित हुआ, जिसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतांत्रिक बनाना और संतुलित करना है।

आज,ब्रिक्स में ग्यारह देश शामिल हैं- ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। यह ग्लोबल साउथ के लिए एक प्रमुख राजनीतिक और राजनयिक मंच बन गया है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सक्षम बनाता है।

एक उदार राजनेता के रूप में, जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध के दौर के सैन्य गुटों-नाटो या वारसॉ पैक्ट के साथ गठबंधन करने से इनकार कर दिया था। उनका उद्देश्य नए स्वतंत्र विकासशील देशों को एकजुट करना था ताकि वे साझेदारी और आपसी स मान के माध्यम से अपनी विकास रणनीतियों को आगे बढ़ा सकें। मार्शल टीटो, गमाल अब्देल नासिर और क्वामे न्क्रूमा के साथ मिलकर, उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। नैम जल्द ही एक शक्तिशाली समूह बन गया जिसमें न केवल विकासशील देश बल्कि क्यूबा और वियतनाम जैसे क युनिस्ट राज्य, और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) जैसे राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन भी शामिल थे।

जबकि पश्चिमी शक्तियां नैम के उपनिवेशवाद विरोधी और साम्राज्यवाद विरोधी रुख से असहज थीं, सोवियत संघ ने आम तौर पर आंदोलन में भारत के नेतृत्व का स्वागत किया। इतिहासकार गोपाल कृष्ण गांधी ने हिंदुस्तान टाइ स में एक लेख में बताया है कि उस समय के एक प्रतिष्ठित राजनेता सी. राजगोपालाचारी के 27 मार्च 1958 के पत्र के बाद, सोवियत संघ ने पांच दिनों के भीतर परमाणु परीक्षणों पर एकतरफा रोक लगा दी। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत यात्रा के दौरान, राष्ट्रपति पुतिन ने दोहराया कि यदि संयुक्त राज्य अमेरिका पारस्परिक आश्वासन देता है तो रूस परमाणु परीक्षण करने से परहेज करेगा - यह घोषणा भारतीय धरती पर की गई है। यह भी प्रासंगिक है कि पूर्व सोवियत संघ ने परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए राजीव गांधी कार्य योजना का समर्थन किया था।

पुतिन की यात्रा के बाद एक ठोस शांति पहल होनी चाहिए। भारत, चीन और रूस मिलकर एशिया में स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पाकिस्तान, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार होने के बावजूद, एक मजबूत सैन्य छाया के तहत काम करना जारी रखे हुए है। फिर भी, उसे एक रचनात्मक संवाद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। भारत को राजनयिक जुड़ाव से पीछे नहीं हटना चाहिए, और सार्क को पुनर्जीवित करने की इच्छा दिखानी चाहिए। केवल संवाद के माध्यम से ही दक्षिण एशिया स्थायी शांति की ओर बढ़ सकता है।

कोई भी भारतीय सरकार- चाहे उसका राजनीतिक झुकाव जो भी हो- को यह पहचानना चाहिए कि क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए एक व्यापक सोच और दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। राष्ट्रपति पुतिन के चीन के साथ करीबी संबंध और पाकिस्तान के साथ उनका व्यावहारिक, गैर-विरोधी जुड़ाव दक्षिण एशियाई पड़ोस में ज़्यादा शांतिपूर्ण माहौल के लिए अवसर बनाने में मदद कर सकता है।

विविध समाचार

केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल को 5000 करोड़ से अधिक की राशि दी, झूठ बोल रही कांग्रेस : भाजपा

शिमला ०४/०१ (संवाददाता): भाजपा के प्रदेश सचिव एवं विधायक विनोद कुमार एवं मीडिया प्रभारी कर्ण नंदा के कहा की प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल की जनता में एक झूठी धारणा पैदा करने का प्रयास कर रही है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहेंगे कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल सरकार के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए हिमाचल को 5000 करोड़ से अधिक की राशि दी, कांग्रेस और उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा की 1 अक्टूबर 2024 को प्रदेश को एनडीआरएफ से मिली 189 करोड़ की मदद मिली थी। गृह मंत्रालय ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से केंद्रीय हिस्से के रूप में और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अग्रिम राशि के रूप में 14 बाढ़ प्रभावित राज्यों

को 5858.60 करोड़ जारी किए थे। 3 अगस्त 2024 को केंद्र ने हिमाचल को दी 61 करोड़ की वित्तीय सहायता दी थी। यह वित्तीय सहायता वर्ष 2021 में शेष रह गई थी, जिसे अब केंद्र सरकार ने जारी किया है। 26 नवंबर 2024 को केंद्र सरकार ने विभिन्न राज्यों के लिए आपदा न्यूनीकरण और क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 1115.67 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को 139 करोड़ रुपए मिलेंगे। 30 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि(एनडीआरएफ) के तहत हिमाचल प्रदेश को 107.15 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता जारी की थी। राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि–1 के अंतर्गत 42 करोड 80 लाख रु 16 मई–एम 2023 को प्राप्त गए थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ)–1 के अंतर्गत 189 करोड़ 27 लाख रु 7 अगस्त 2023 को प्राप्त हुई थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड (एनडीआरएफ) –2 के अंतर्गत 200 करोड़ रू 21 अगस्त 2023 को प्राप्त हुए थे। 12 दिसंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रू की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी दी थी। 6 अक्टूबर 2024, हिमाचल सरकार के खाते में एनडीआरफ और एसडीआरएफ के मंजूर 189. 20 करोड़ रुपये आ गए थी। केंद्र सरकार ने ये राशि राज्य में 2023 के मॉनसून के दौरान आई आपदा के लिए दी है। उन्होंने कहा कि भौगोलिक जटिलताओं के कारण हिमाचल प्रदेश लगभग हर वर्ष प्राकृतिक आपदा की मार झेलता है। हिमाचल में आपदा के दौरान मैं 3 बार केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मिलकर भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मदद से प्रदेश के लिए 16,206 हजार घर आवास योजना के अन्तर्गत व 2373 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली 2700 किमी. की सड़कें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत मंजूर करवाईं थी। 1 अप्रैल 2025 को हिमाचल में साल 2023 में आई आपदा में ध्वस्त हुए 21 पुलों का नए सिरे से निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (चरण–3) के तहत 140.90 करोड़ रुपये से ये पुल बनाए जाएंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 126.81 करोड़ रुपये स्वीकृत कर दिए हैं। 5 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने हिमाचल में वर्ष 2024 में प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 136.22 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि 18 जुलाई 2025 को देवभूमि में संकट से निपटने तथा आपदा पीड़ितों को केंद्र सरकार से मिले 2006.40 करोड़, जेपी नड्डा ने पीएम का धन्यवाद किया।

हिमाचल में सत्संग से लौट रही श्रद्धालुओं की बस खाई में गिरी, 32 यात्री घायल

बिलासपुर ०४/०१ (संवाददाता): हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। इस भीषण हादसे में 32 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी एम्स और जिला अस्पताल बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू घायलों का हाल जानने बिलासपुर पहुंचे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, बस में सवार सभी श्रद्धालु पंजाब से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक सत्संग में शामिल होने के बाद अपने घर लौट रहे थे। बस में कुल 36 लोग सवार थे, जिनमें से अधिकांश सोलन क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। यह हादसा देर रात करीब 3रू15 बजे बिलासपुर के नम्होल के पास हुआ। बस के खाई में गिरते ही यात्रियों में चीख–पुकार मच गई। आसपास के स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकाला। रात में घना अंधेरा होने के कारण बचाव एवं राहत कार्य में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एम्स बिलासपुर पहुंचकर सभी घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को घायलों का सर्वोत्तम और शीघ्र उपचार सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार की ओर से हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान उनके साथ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी समेत स्थानीय प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बरमाणा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। बस चालक को भी मार्कंड के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पंजाब विधानसभा सत्र : बेअदबी पर कानून लाएगी सरकार

चंडीगढ़ ०४/०१ (संवाददाता): पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन शुक्रवार को विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत हंगामे के साथ हुई। विपक्षी कांग्रेस विधायकों ने पहले प्रश्नकाल को टालने और सीधे प्रस्ताव पेश करने के विरोध में सदन से वॉकआउट कर दिया। सरकार की ओर से भाखड़ा और अन्य डैमों पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तैनाती के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। यह प्रस्ताव जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने सदन में रखा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इन डैमों पर CISF की तैनाती को मंजूरी दी थी, जिसे मौजूदा सरकार खारिज करती है। विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि "भाखड़ा डैम पर CISF हटाने की बात करने वाली सरकार खुद सचिवालय में बैश्ठ की तैनाती कर रही है। क्या वहां मंत्रियों को अपनी सुरक्षा का डर है?"इस बीच, सरकार ने शुक्रवार को बेअदबी के मामलों को रोकने के लिए विशेष कानून लाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह कानून सभी धर्मों के प्रतिनिधियों, धार्मिक संगठनों और जनता से सुझाव लेने के बाद तैयार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी और सभी कानूनी प्रावधानों का ध्यान रखा जाएगा। सीएम मान ने यह भी बताया कि कांग्रेस सरकार के समय डैमों पर CISF की तैनाती को मंजूरी दी गई थी, जिसे अब रद्द करने के लिए विशेष प्रस्ताव लाया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि गांवों के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 1500 महिला सरपंचों और पंचों को पवित्र स्थल श्री हजूर साहिब, नांदेड़ के दर्शन के लिए भेजा जाएगा।

अपराधियों पर पंजाब पुलिस का चाबुक, कहीं हैरोइन बरामद कहीं मुठभेड़ के बाद हथियार पकड़े

चंडीगढ़ ०४/०१ (संवाददाता): अपराधियों खासतौर पर नशा तस्करों पर पंजाब पुलिस ने मोर्चा खोला हुआ है। इसी के तहत फिरोजपुर पुलिस ने रछपाल सिंह उर्फ घ्घगोरा पुत्र सुखमंदर सिंह निवासी बस्ती मच्छियां नजदीक माता दा मंदिर थाना सिटी जीरा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की ड्रग मनी बरामद की है।

गुप्त सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ जीरा की टीम चुरस्था टिंडवा–चोहला में बने बस स्टैंड पर पहुंची तो वहां एक युवक किट बैग पहने खड़ा दिखाई दिया, जो पुलिस पार्टी को देखकर खिसकने लगा, जिसे शक के आधार पर काबू कर लिया गया और तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम हेरोइन और 2 लाख रुपये की भारतीय करेंसी ड्रग मनी बरामद की गई, जिस संबंध में थाना सदर जीरा में मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह अमृतसर के गेट हकीमा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया है। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर स्थिति का जायजा लेने के लिए मुठभेड़ स्थल पर पहुंच रहे हैं। 25 जून को ढिलवां टोल प्लाजा पर टोल पर्ची बचाने के लिए चार व्यक्तियों द्वारा की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर आज सुबह ढिलवां मंड इलाके में भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रमनदीप सिंह कथू नंगल अमृतसर और उसके साथी अमृतसर निवासी के रूप में हुई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला पुलिस प्रमुख गौरव तूरा ने बताया कि ढिलवां मंड इलाके में हथियारों की बरामदगी के दौरान एक आरोपी रमनदीप सिंह ने कथित तौर पर पुलिस कर्मियों को धक्का देकर भागने की कोशिश की, मुठभेड़ के दौरान उसके पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सिविल अस्पताल कपूरथला में भर्ती कराया गया। पंजाब सरकार द्वारा शुरू की गई 'नशे के खिलाफ जंग' मुहिम के तहत एसएसपी बरनाला मोहम्मद सरफराज आलम ने नशा तस्करी के आरोप में नामजद उषा रानी पत्नी बीरबल की दुकान को ध्वस्त कर दिया। इस मौके पर एसपी (डी) अशोक कुमार, डीएसपी सतवीर सिंह बैंस, जिला मंडी अधिकारी बीरिंदर सिंह, एसएचओ धनौला जगदीप सिंह भी मौजूद थे।

"मैं व्यापारियों के साथ हूं" : फगवाड़ा गेट पर जीएसटी रेड के बाद नितिन कोहली व्यापारियों और जीएसटी अधिकारियों से करेंगे मुलाकात

जालंधर ०४/०१ (संवाददाता): जालंधर के फगवाड़ा गेट मार्केट में एक मोबाइल दुकान पर अचानक हुई जीएसटी रेड के बाद व्यापारियों में भारी रोष फैल गया और विरोधस्वरूप कई दुकानदारों ने बाजार बंद कर दिया। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के जालंधर सेंट्रल हलके इंचार्ज और उद्योगपति नितिन कोहली, जो इस समय विदेश में हैं, ने व्यापारिक समुदाय के साथ एकजुटता जताते हुए कड़ा बयान जारी किया। नितिन कोहली ने कहा, "मैं इस समय विदेश में हूं, इसलिए रेड के समय व्यापारियों की मदद नहीं कर सका, लेकिन भारत लौटते ही मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित व्यापारियों और जीएसटी अधिकारियों से मिलूंगा ताकि दोनों पक्षों की बात सुनकर व्यावहारिक और निष्पक्ष समाधान निकाला जा सके।" उन्होंने आश्वासन दिया कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह से व्यापारियों और छोटे दुकानदारों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, "मैं खुद एक उद्योगपति हूं और व्यापारिक समुदाय के साथ खड़ा हूं। आप सरकार ने पहले ही कई व्यापार–मित्र नीतियां लागू की हैं, जो छोटे वेंडरों से लेकर बड़े रिटेलर्स तक को लाभ पहुंचा रही हैं।" कोहली ने यह भी स्पष्ट किया कि वे जीएसटी से जुड़े मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे और मुद्दे का समाधान निकालने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देगी। मैं स्वयं निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित करूंगा और व्यापार को बढ़ावा देने वाले समाधान लागू करवाने में सहयोग करूंगा।" नितिन कोहली ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी सरकार ने 'इंस्पेक्टर राज' को खत्म कर दिया है और राज्य में व्यापार करना आसान बनाने के लिए निरंतर नीतियां ला रही है। उन्होंने कहा, "स्ट्रीट वेंडरों से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हम हर हितधारक के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

जून 2025 में भगवंत मान सरकार ने पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 में बड़ा संशोधन पारित किया था, जिससे 95: छोटे व्यवसायों पर से अनुपालन का बोझ कम हुआ और व्यापार करना और आसान बना।

पंजाब विधानसभा में बीबीएमबी से सीआईएसएफ हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित, पशु क्रूरता पर भी बिल पास, जमकर हुई बहस

चंडीगढ ०४/०१ (संवाददाता): पंजाब विधानसभा के स्पेशल सेशन के दूसरे दिन कई प्रस्तावों को सर्वसम्मति के साथ पारित किया गया है। सरकार ने डैमों की सुरक्षा से बैश्ठ को हटाने संबंधी 5 बिल पेश किए गए है। बीबीएमबी से सीआईएसएफ हटाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। वहीं, धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर महत्वपूर्ण बिल कर ड्रॉफ्ट सरकार द्वारा पेश किया गया है। इसी के साथ विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह सिंधवां ने जानकारी दी कि सत्र का समय बढ़ा कर 15 जुलाई कर दिया गया है। बीबीएमबी (भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड) में सीआईएसएफ की तैनाती न करने संबंधी प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब इस मुद्दे को लेकर पंजाब सरकार केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाएगी और मांग करेगी कि सीआईएसएफ की तैनाती का फैसला वापस लिया जाए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में कहा कि पंजाब पुलिस पूरी तरह काबिल और सक्षम है, जो डैमों की सुरक्षा भी खुद कर सकती है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सीआईएसएफ की तैनाती हटाने संबंधी प्रस्ताव पास किया जाना चाहिए। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम मान ने कहा, "हम जितना समय है, इस तरह आपको तंग करेंगे। लोगों से वोट डालकर हटवा दो। दिल्ली में हमारी सरकार दस साल रही है, वहां पर इनकी जीरो है। न्यू दिल्ली में ही इनके नेताओं के बड़े–बड़े घर हैं, लेकिन अब वहां के माली भी इन्हें वोट नहीं डालते। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, अखबारों में बॉक्स लगवाते हैं, जनाब 60 साल आपको सुना है, अब हमें भी सुन लो।" नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा आपको पूरा टाइम मिलेगा। चेयर पर स्प्रिंग लगी है, एकदम खड़े हो जाते हैं। हमें मेटेरियल कहते हैं और फिर कहते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम है।" विधानसभा में पशु क्रूरता संशोधन बिल सर्वसम्मति से पास किया गया है। पक्ष विपक्ष के नेताओं के साथ हुई बातचीत के बाद ये बिल पास हुआ। सीएम ने विधानसभा में पशु क्रूरता संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान संत राम उदासी की रचना की कुछ पंक्तियां पढ़कर सुनाईं और कहा कि लोग तोते, कबूतर और कुत्ते पालते हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों में तो इन जानवरों के सबसे महंगे ऑपरेशन

तक कराए जाते हैं। सीएम ने बताया कि पंजाब में गडवासू जैसी संस्थाएं मौजूद हैं और इस बिल के पारित होने से पूरे पंजाब में बैलों के खेल आसानी से आयोजित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनके अपने गांव में भी ऐसा टूर्नामेंट होता है और लुधियाना, कपूरथला और तरनतारन सहित कई जिलों में ये पारंपरिक खेल आज भी खेले जाते हैं। गांवों की इन पारंपरिक खेलों को हमारी विरासत बताते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें संरक्षित रखना चाहिए। वहीं, आवारा कुत्तों के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि यह एक गंभीर समस्या है, जब कुत्ते बच्चों और बुजुर्गों को घेर लेते हैं तो बहुत दुख होता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। सीएम भगवंत मान ने पशु क्रूरता संशोधन विधेयक पर बोलते हुए कहा कि पहली बार बेजुबानों के हक में आवाज उठाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सर बैलों की जोड़ी हमारे लिए खास महत्व रखती है, हमारे गुरु साहब ने भी करतारपुर साहिब में 16 साल तक बैलों से खेती की थी। सीएम ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि वह जानवरों को अपने बेटों की तरह पालते हैं। सीएम ने तमिलनाडु की जल्लीकट्टू और पंजाब की बैलों की दौड़ की तुलना करते हुए कहा कि दोनों एक जैसी परंपराएं हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस विधेयक में एक अहम शर्त रखी गई है कि दौड़ के दौरान पशुओं को डंडा या किसी और चीज से मारा नहीं जाएगा, केवल हाथ से थपथपा कर उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा।

Printed, Published,Edited, & Owned by Prakash Kumar Dhal, Printed at Promodini Publication, Main road , Chhend colony , Rourkela-15 & Published at ECR-73, Chhend Colony, Rourkela-15, Editor : Prakash kumar Dhal, Email:kalingasamachar@gmail.com , Mob: 9439951525, Ph. 0661-2646999

ओडिशा समाचार

कलिंग समाचार | राउरकेला, सोमवार 05 जनवरी 2026 | पृष्ठ-6

भाजपा गांधी और राम का इस्तेमाल प्रोपेगैंडा के लिए करती है, आदर्शों पर नहीं चलती-सुरजेवाला

भुवनेश्वर ०४/०१ (संवाददाता): ग्रामीण नौकरी गारंटी कानून मनरेगा को विकसित भारत-जी राम जी से बदलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए, कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि भाजपा न तो महात्मा गांधी और न ही भगवान राम का सज़्मान करती है, और उनका इस्तेमाल प्रोपेगैंडा के लिए करती है। शनिवार को भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, सुरजेवाला ने दावा किया कि क्क के समय के मनरेगाको विकसित भारत-गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एज़्ट से बदलने से लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा, पिछले 11 सालों में, महात्मा गांधी का चश्मा प्रोपेगैंडा के लिए उधार लिया गया है, लेकिन उनके आदर्शों को नज़रअंदाज़ किया गया। इसी तरह, भाजपा ने भगवान राम के नाम पर सज़ा हथिया ली, लेकिन उनके आदर्शों को नज़रअंदाज़ कर दिया।

भाजपा इसी तरह से सरकार चलाती है। उन्होंने दावा किया कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एज़्प्लॉयमेंट गारंटी एज़्ट को बदलने से लगभग 12.5 करोड़ गरीब, आदिवासी, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों पर सीधा असर पड़ा है।

उन्होंने दावा किया, उनके परिवार के सदस्यों को मिलाकर, भाजपासरकार के इस फैसले से कुल 50 करोड़ लोगों पर असर पड़ा है। सुरजेवाला ने कहा कि मनरेगा एक डिमांड पर चलने वाला सिस्टम था, और कोई भी मज़दूर पंचायत से संपर्क करके काम मांग सकता था। उन्होंने कहा, अगर कुछ दिनों में काम नहीं मिलता था, तो मज़दूरी देनी पड़ती थी। यही मनरेगा था। हालांकि, नए कानून के तहत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि सब कुछ दिल्ली से तय होगा। दिल्ली में बैठे लोग बताएंगे कि किस राज्य, जिले या गांव को कितना काम मिलेगा। कांग्रेस क्क ने कहा कि मनरेगा पूरी तरह से केंद्र से फंडेड है, लेकिन विकसित भारत-जी राम जी के तहत राज्यों को 40 परसेंट खर्च उठाना होगा।

उन्होंने दावा किया, जैसा कि हम जानते हैं, राज्य 40 परसेंट फंड नहीं दे सकते, इसलिए गरीबों को काम देने का आइडिया अपने आप बंद हो जाएगा। स्टेट कांग्रेस इंचार्ज अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पार्टी 10 जनवरी को ओडिशा में 'मनरेगा बचाओ संग्राम' शुरू करेगी और यह 25 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा, गरीब लोगों पर असर डालने वाले नए कानून का विरोध करते हुए जिले से लेकर स्टेट लेवल तक पज़्लिक मीटिंग की जाएंगी।

यातायात एवं कच्चा माल विभाग में नई 60-टन क्षमता की बीओबीएसएन वैगनों का उद्घाटन

राउरकेला ०४/०१ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के यातायात एवं कच्चा माल (टी एंड आरएम) विभाग में नवप्रवेशित 60 टन क्षमता की तीन बीओबीएसएन वैगनों का उद्घाटन 23 दिसंबर, 2025 को कार्यपालक निदेशक (संकार्य), श्री विश्वरंजन पलई द्वारा किया गया। ई-215, ई-216 एवं ई-217 कॉल नंबर वाली इन वैगनों का उद्घाटन मुज़्य महाप्रबंधक (अनुरक्षण), श्री एस एस रॉयचौधरी, मुज़्य महाप्रबंधक (यांत्रिकी), श्री डी के पालो तथा मुज़्य महाप्रबंधक (टी एंड आरएम), श्री कौशिक सुन्यानी की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर टी एंड आरएम तथा संबंधित विभागों के कई वरिष्ठ अधिकारी एवं बड़ी संज़्या में कर्मचारी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री पलई ने संयंत्र के आंतरिक लॉजिस्टिज़्स को सुदृढ़ करने तथा परिचालन दक्षता बढ़ाने की दिशा में सतत एवं केंद्रित प्रयास जारी रखने का आह्वान किया, जो संयंत्र के उत्पादन प्रदर्शन को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय है कि, आरएसपी में तैयार एवं अर्ध-तैयार उत्पादों, उप-उत्पादों तथा इस्पात निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक कच्चे माल के परिवहन हेतु लगभग 500 आंतरिक रोलिंग स्टॉक वैगनों का संचालन किया जाता है। इन वैगनों का अनुरक्षण टी एंड आरएम विभाग के कैरिज एवं वैगन अनुभाग द्वारा किया जाता है। कुल बेड़े में से 106 वैगन बीओबीएसएन (एचबी) प्रकार के हैं।एएमआर योजना के अंतर्गत सामग्री चालन क्षमता को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आरएसपी ने मेस्सर्स सेल ग्रोथ वर्क्स (एसजीडज़्ल्यू), कुल्टी को 60-टन क्षमता की 39 बीओबीएसएन वैगनों की आपूर्ति हेतु आदेश दिया है। उद्घाटित वैगन इस खेप की प्रथम तीन इकाइयाँ हैं। प्रत्येक बीओबीएसएन वैगन की लागत लगभग 61.8 लाख रुपये है, जबकि सभी 39 वैगनों पर कुल निवेश 2410.26 लाख रुपये है।

गौरतलब है कि, बीओबीएसएन वैगनों का उपयोग एमबीसी, पीएचसी, हार्ड कोक, ब्रीज़ कोक, नट कोक, कोयला, सिन्टर, मिल स्केल, बॉयलर कोल, एलडी फाइंस, (-30 - माइनस 30) चुना पत्थर आदि विभिन्न प्रक्रमाधीन सामग्रियों के आंतरिक परिवहन के लिए किया जाता है, जिससे आरएसपी में निर्बाध उत्पादन संचालन सुनिश्चित हो पाता है।

पहली ओरल पिल मिटापिवेट थैलेसीमिया मैनेजमेंट में ला सकती है क्रांति

भुवनेश्वर ०४/०१ (संवाददाता): ऐसा लगता है कि नए साल ने थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए एक बड़ी सफलता लाई है, ज़्योंकि अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (स्वष्ठ) ने इस आनुवंशिक खून की बीमारी से पीड़ित वयस्कों के इलाज के लिए पहली ओरल गोली को मंज़ूरी दे दी है। दवा मिटापिवेट ने ज़्लड ट्रांसज़्यूजन पर निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण क्षमता दिखाई है।

मिटापिवेट एक पाइरूवेट काइनेज एज़्टिवेटर है। चूंकि PK एंजाइम लाल रक्त कोशिकाओं में एनर्जी प्रोडज़्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मिटापिवेट को लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एनर्जी बैलेंस को बेहतर बनाने और आनुवंशिक हेमोलिटिक एनीमिया वाले मरीज़ों की मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

हेमेटोलॉजिस्ट और बोन-मैरो ट्रांसप्लांट डॉज़्टरों के अनुसार, यह दवा लंबे समय तक बीमारी के मैनेजमेंट को बदल सकती है। थैलेसीमिया एक आम आनुवंशिक हीमोग्लोबिन विकार है जो अल्फा, बीटा या डेल्टा ग्लोबिन जीन में ज़्यूटेशन के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप हीमोग्लोबिन सिंथेसिस खराब होता है और एरिथ्रोपोएसिस अप्रभावी होता है। यह पूर्वी भारत में एक बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है, ओडिशा ऐसे हीमोग्लोबिनोपैथी, जिसमें सिकल सेल रोग भी शामिल है, के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्यों में से एक है।

बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और उभरती जीन थेरेपी जैसे उन्नत उपचार विकल्पों के बावजूद, मरीज़ सीमित पहुंच, ज़्यादा लागत और डोनर की अनुपलज़्धता के कारण नियमित ज़्लड ट्रांसज़्यूजन पर निर्भर रहते हैं। इंडियन कॉलेज ऑफ हेमेटोलॉजी के सचिव और ज़िलनिकल हेमेटोलॉजी विभाग के पूर्व प्रमुख प्रो. आरके जेना ने स्वष्ठ की मंजूरी को एक संभावित गेम-चेंजर बताया और कहा कि यह दवा मरीज़ों के नतीजों में काफी सुधार कर सकती है। उन्होंने कहा, मरीज़ों में बार-बार ज़्लड ट्रांसज़्यूजन से अज़्सर आयरन ओवरलोड और लिवर, दिल और एंडोक्राइन सिस्टम जैसे महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान होता है। अगर कोई ओरल दवा ट्रांसज़्यूजन की ज़रूरतों को काफी कम कर सकती है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। प्रो. जेना, जो एक शक्तिशाली हीमोग्लोबिन इंड्यूसर के रूप में थैलिडोमाइड पर भारत के पहले अध्ययन का हिस्सा थे, ने बेहतर चिकित्सीय परिणाम प्राप्त करने के लिए मिटापिवेट को थैलिडोमाइड के साथ शुरू करने का सुझाव दिया। थैलिडोमाइड, जो अपने इज़्यूनोमॉड्यूलेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, ने ज़रूण हीमोग्लोबिन उत्पादन को बढ़ाकर ट्रांसज़्यूजन पर निर्भरता को कम करने में उत्साहजनक परिणाम दिखाए हैं। उन्होंने कहा, बीटा थैलेसीमिया मेजर या इंटरमीडिया वाले दो से 18 साल की उम्र के 404 मरीज़ों में थैलिडोमाइड की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया गया है। यह उन मरीज़ों के लिए एक सुविधाजनक, प्रभावी और किफायती विकल्प प्रदान करता है जो एलोजेनिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के लिए योग्य नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉलेज ऑफ़ हेमेटोलॉजी ने पहले ही थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए शरीर के वज़न के प्रति किलोग्राम दो से चार मिलीग्राम की डोज़ में थैलिडोमाइड के इस्तेमाल की सलाह दी है।

बार के अंदर हंगामा करने और जबरन वसूली करने के आरोप में चार लोग गिरफ्तार

भुवनेश्वर ०४/०१ (संवाददाता): मंचेश्वर पुलिस ने शहर के पलासुनी इलाके के एक बार में हिंसक हंगामे और जबरन वसूली की कोशिश के सिलसिले में चार लोगों को गिरज़्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। यह घटना 1 जनवरी, 2026 की रात को मंचेश्वर पुलिस की सीमा के तहत रसूलगढ़ में एक बार के पास हुई। पुलिस ने जिन आरोपियों की पहचान की है, वे हैं पूर्ण चंद्र शियाल (25), देबी प्रसाद बारिक (21), प्रियब्रत खटुआ (22) और आशुतोष मोहंती। पुलिस के मुताबिक, चारों आरोपी, दो अन्य लोगों के साथ, नशे की हालत में रसूलगढ़ के पास एक बार में घुसे और बार स्टाफ से पैसे मांगे। जब वेटर ने विरोध किया और उनसे ग्राहकों के सामने हंगामा न करने को कहा, तो आरोपियों ने हंगामा किया और बार के सामान को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कथित तौर पर बार के अंदर परफॉर्म कर रही एक महिला सिंगर के साथ भी बदतमीजी की। भरोसेमंद जानकारी के आधार पर, पुलिस ने चार आरोपियों को गिरज़्तार किया, जिन्होंने बाद में पूछताछ के दौरान अपनी संलिप्तता कबूल कर ली। हालांकि, घटना में शामिल दो अन्य आरोपी फरार हैं।

कंस की प्रतीकात्मक मृत्यु के साथ हुआ विश्व प्रसिद्ध बरगढ़ धनु यात्रा का समापन

बरगढ़ ०४/०१ (संवाददाता): विश्व प्रसिद्ध 11 दिवसीय बरगढ़ धनु यात्रा का शनिवार को राजा कंस के प्रतीकात्मक वध के साथ समापन हुआ। भगवान कृष्ण द्वारा कंस का वध अत्याचार पर सत्य और न्याय की विजय का प्रतीक था, जिसके बाद महाराजा उग्रसेन का राज्याभिषेक हुआ, जो धर्मी शासन की बहाली का संकेत था।

समापन दिवस पर, पारंपरिक अनुष्ठान के अंतर्गत भगवान कृष्ण और बलराम ने मथुरा की यात्रा की । बाद में, सेनापति सत्यकी भगवान कृष्ण को राजा कंस के दरबार तक ले गए। हालांकि, हाथी कुवलय ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया, जिससे नाटकीयता और बढ़ गई। बाद में, पौराणिक कथा के अनुसार, कृष्ण और बलराम ने हाथी का वध कर दिया।

नाटक का चरमोत्कर्ष एक भयंकर युद्ध के साथ हुआ जिसमें अष्टमल्ला को दिव्य भाइयों ने मार डाला। इन घटनाओं से विचलित होकर राजा कंस की चिंता बढ़ती गई, तभी कृष्ण और बलराम ने राज दरबार में प्रवेश किया। चाचा-भतीजे के प्रतीकात्मक द्वंद्व में अत्याचारी राजा कंस अंतत: पराजित हुआ और दरबार में ही गिर पड़ा, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक था।

इस भव्य प्रस्तुति ने लाखों दर्शकों को आकर्षित किया, जिसमें ओडिशा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया गया। समापन के बाद, कंस का चरित्र प्रतीकात्मक रूप से पुरी की यात्रा पर गया, जहां उसने समुद्र में पवित्र स्नान किया और भगवान जगन्नाथ से आशीर्वाद मांगा, इस प्रकार क्षमा की सदियों पुरानी परंपरा को पूरा किया।

मोहन माझी ने आयुर्वेदिक, होज़्योपैथिक कॉलेजों में पीजी छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाया

भुवनेश्वर ०४/०१ (संवाददाता): मुज़्यमंत्री मोहन चरण माझी ने ओडिशा के सरकारी आयुर्वेदिक और होज़्योपैथिक कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे पोस्टग्रेजुएट छात्रों के स्टाइपेंड में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस कदम का मकसद छात्रों को आयुर्वेद और होज़्योपैथिक मेडिसिन में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। नई दरों के अनुसार, जो 1 जनवरी, 2026 से लागू होंगी, पहले साल के क्क्त छात्रों का मासिक स्टाइपेंड 55त्न बढ़कर 31,000 रुपये से 48,000 रुपये हो जाएगा। दूसरे साल के छात्रों के लिए यह 62त्न बढ़कर 32,000 रुपये से 52,000 रुपये हो जाएगा। तीसरे साल के छात्रों के लिए स्टाइपेंड की रकम 67त्न बढ़कर 33,000 रुपये से 55,000 रुपये हो जाएगी। इसके अलावा, हाउस सर्जन का स्टाइपेंड 1 अगस्त, 2024 से 17,000 रुपये से बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया जाएगा। मुज़्यमंत्री ने उज़्मीद जताई कि इस कदम से छात्र अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाएंगे और अच्छी हेल्थकेयर सेवाएं दे पाएंगे। आयुर्वेद और होज़्योपैथी में क्क्त कोर्स कर रहे लगभग 120 छात्रों को इस फैसले से फायदा होगा।

दीपिका महिला संघति द्वारा भव्य वार्षिक मेले-2025 का आयोजन

राउरकेला ०४/०१ (संवाददाता): दीपिका महिला संघति का वार्षिक भव्य मेला राउरकेला ज़्लब में आयोजित किया गया। राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी) के निदेशक प्रभारी (डीआईसी) श्री आलोक वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अध्यक्ष, दीपिका महिला संघति, श्रीमती नम्रता वर्मा, कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन); श्री तरुण मिश्र, श्री बी के गिरी, कार्यपालक निदेशक (खान विकास-सीएमएलओ), कार्यपालक निदेशक (संकार्य); श्री बिस्वरंजन पलई, कार्यपालक निदेशक (सामग्री प्रबंधन), श्री अनिल कुमार, श्री एम पी सिंह, कार्यपालक निदेशक (खान, ओजीओएम-सीएमएलओ), दीपिका महिला संघति की उपाध्यक्षाएँ, श्रीमती प्रभाती मिश्र; डॉ. (श्रीमती) प्रतिज्ञा पलई; श्रीमती रीता रानी, संघति की सचिव, श्रीमती सारिका कुमार, राउरकेला इस्पात संयंत्र के अनेक वरिष्ठ अधिकारी, शासी निकाय के सदस्य तथा संगठन के अन्य सदस्य उपस्थित थे। निदेशक प्रभारी सहित अन्य अतिथियों एवं गणमान्यों ने सभी स्टॉलों का भ्रमण किया और उनमें गहरी रुचि दिखाई।

बिरयानी, फास्ट फूड से लेकर पारंपरिक नाश्ते एवं बेकरी आइटज़्स तक के स्वादिष्ट व्यंजनों वाले स्टॉलों ने भारी भीड़ को आकर्षित किया। खेल, लकी ड्रॉ और हाउजी ने युवाओं एवं युवा मन वालों को विशेष रूप से आकर्षित किया, जिनमें निपुणता, कौशल, रचनात्मकता, सूझ-बूझ और भाग्य की भी परीक्षा हुई। परिधान, वस्त्र एवं अन्य उपभोग्य सामग्री के स्टॉल भी मेले का अहम हिस्सा रहे। आरएसपी के राजभाषा विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल ने भाषा प्रेमियों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। आगामी राउरकेला हाफ मैराथनङ्क2026 के प्रचार हेतु लगाए गए स्टॉल पर इसके शुभंकर राजा और पद्मा तथा ट्रेडमिल पर चलने की प्रतियोगिता लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। आरएसपी के अग्निशमन विभाग ने अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अपने स्टॉल के माध्यम से साधारण तौर पर काम आने वाले अग्निशमन उपकरणों का प्रदर्शन किया। इसी प्रकार, आरएसपी के बागवानी विभाग और ओडिशा सरकार के वन विभाग के स्टॉल ने मानव-पशु द्वंद के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। संध्या के समय आरएसपी की निनाद संगीत मण्डली द्वारा प्रस्तुत संगीत कार्यक्रम ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेले को राउरकेलावासियों से अत्यंत उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली और उन्होंने इस शाम का भरपूर आनंद उठाया।

उल्लेखनीय है कि दीपिका महिला संघति महिला सशक्तिकरण, गरीब बच्चों की शिक्षा तथा समाज के वंचित और हाशिए पर पड़े वर्गों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलज़्ध कराने जैसी बहुआयामी गतिविधियों में संलग्न है। श्रीमती नम्रता वर्मा के नेतृत्व में संघति के समर्पित सदस्य राउरकेला एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में अनेक सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। मेले से प्राप्त आय संघति द्वारा संचालित विभिन्न परोपकारी एवं कल्याणकारी कार्यों में उपयोग की जाएगी।